

विविध-

दवाई के साथ कितना पानी...

विचार-

एक ही मुद्दे पर दो समानांतर मोर्चे

खेल-

आईपीएल 2027: अजिंक्य रहाणे भी...

किसमें कितना है दम , योगी की चुनौती

अखिलेश अयोध्या से लड़ें, मैं भी लड़ता हूं, हो जाए आमने-सामने का मुकाबला

बलरामपुर (संवाददाता)। यूपी के बलरामपुर में उत्तरौला के कालूबनकट में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 803 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए।

कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। सीएम ने लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक सौंपकर उन्हें योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही।

सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या से चुनाव लड़ें, हम भी लड़ेंगे। आमने-सामने मुकाबला हो जाए और तय हो जाए कि



किसमें कितना दम है। तंज कसते हुए कहा कि माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले उनसे क्या लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान से समारोह में सियासी माहौल गरमा गया।

सीएम ने अयोध्या के प्रति अपनी आस्था जाहिर करते हुए कहा कि वह बार-बार अयोध्या जाते हैं। अयोध्या उनके लिए पावन धाम है। वहां विकास कार्यों में किसी तरह की कोताही नहीं

होनी चाहिए। अयोध्या केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इसके विकास को लेकर सरकार गंभीर है और लगातार काम कराया जा रहा है।

सपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि विपक्षी नेता विकास के मुद्दे पर घिरने के बाद चुनौती देने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे मुकाबले के लिए

ललकारते हुए कहा कि आमने-सामने की लड़ाई से साफ हो जाएगा कि किसमें कितना दम है।

सीएम ने अयोध्या में धार्मिक स्थलों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पहले जय श्रीराम के उद्घोष पर रोक लगाई थी, वे आज अयोध्या के विकास पर सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या, काशी और मां विंध्यवासिनी धाम में हो

रहे विकास कार्यों का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अयोध्या उनके लिए आस्था का विषय है और वहां विकास कार्यों में कोई ढिलाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बलरामपुर की विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी काम कर रही है।

इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। बलरामपुर में चल रही विकास परियोजनाएं इसका प्रमाण हैं। पिछले 10 वर्षों में जिले में हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए धनराशि भेजी गई है। इससे जिले में विकास की नई संभावनाएं बढ़ी हैं।

सीजेपी के प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, कई नेता हिरासत में

नयी दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे सहित अन्य मांगों में शनिवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं माकपा के एमए बेबी, तुषमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने बार्डर सहित कई इलाकों में पहरा सख्त करते हुए कई जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी और सुबह से ही यातायात पर कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गईं। वाहनों की आजावाही को नियंत्रित करने



और स्थिति पर निगरानी रखने के लिए प्रमुख चौराहों पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कर्नाट प्लेस, मंडी हाउस, जंतर-मंतर, पटेल चौक और मध्य दिल्ली के अन्य हिस्सों में यातायात जाम और रूट डायवर्जन की चेतावनी देते हुए एडवाइजरी जारी की। पुलिस की सख्ती के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जगह जगह पहुंचे। इनमें मिटो ब्रिज, दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रभावित चौराहों और मार्गों में अशोक रोड-जंतर-मंतर रोड गोल चक्कर, डॉलरस्टॉय मार्ग-जनपथ क्रॉसिंग, जय सिंह रोड-संसद मार्ग क्रॉसिंग, रेल भवन गोल

चक्कर, गोल डाकखाना और विंडसर प्लेस शामिल हैं। पुलिस ने सीजेपी संस्थापक सर्वश्री दीपके, दास और रांका को राष्ट्रीय राजधानी में तब हिरासत में ले लिया जब वे मुंबई से यहां आए हवाई जहाज से उतरने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने उनको विमान के भीतर से अपनी हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद पार्टी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इन नेताओं के हिरासत में लिए जाने के बाद संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे शनिवार को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

खरगे का केंद्र पर हमला, कहा

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे, 500 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को मोदी सरकार पर हमला बोला। उनका यह हमला दिल्ली पुलिस की ओर से लोगों को हिरासत में लिए जाने की वजह से है। उन्होंने कहा कि उसने श्लोकतंत्र की जननीश को श्दबे हुए लोकतंत्र में बदल दिया है। कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि आज भाजपा-आरएसएस की कायरता पूरी तरह से सामने आ गई है। खरगे ने एक्स पर कहा, हमारे युवा, छात्र, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संघ के नेता, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर — यानी जो कोई भी इस सरकार



से सवाल पूछ रहा है। उसे हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, श्मोदी सरकार ने श्लोकतंत्र की जननीश को श्दबे हुए लोकतंत्र में बदल दिया है। कांग्रेस प्रमुख ने जोर देकर कहा कि हिरासत, गिरफ्तारी, जेल, लाठी

और पैलेट गन भारत के लोगों को रोक नहीं सकते। आजादी की लड़ाई के समय से ही देश का भविष्य तय करने में युवा सबसे आगे रहे हैं।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, एकजुट विपक्ष के साथ

मिलकर, इस अत्याचारी शासन का पुरजोर विरोध करेगी। हमने भारत की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। हम अपने लोकतंत्र, अपने संविधान और हर भारतीय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे।

उनके ये बयान तब आए जब प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जो सीईसी के खिलाफ सीजेपी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

नयी दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन ने इंडिया गठबंधन और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को अराजकता वादी समूह बताते हुए उन पर देश को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि देश की जनता और भाजपा कार्यकर्ता उनकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। श्री नवीन ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर सीजेपी के प्रदर्शन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश में बहुत खतरनाक और गंभीर स्थिति

पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। जहां 140 करोड़ लोग शांति और सद्भाव से रह रहे हैं और देश के विकास में मिलकर योगदान दे रहे हैं। वहीं, कुछ लोग देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये काम दो समूह कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और दूसरा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों के नेतृत्व वाली सीजेपी शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, मैं इन

दोनों समूहों से साफ तौर पर



कहना चाहता हूं कि भारत की जनता आपके इरादों को अच्छी तरह समझती है। देश में कौन ज्यादा अस्थिरता पैदा कर सकता है, इसे लेकर आपकी अराजकता की होड़ सफल

नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया है और जनता के फैसले को स्वीकार करने या उससे सीखने के बजाय देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत और विदेशी ताकतों के इशारे पर जो कोशिशें कर रहे हैं, वह सफल नहीं होगी। श्री नवीन ने कहा कि लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और यह बात इन लोगों को खटक रही है।

क्या चंबल के डाकू हैं छात्र?

दीपके की हिरासत पर भड़के माता-पिता, कहा- सरकार को लोकतंत्र का सम्मान नहीं

मुंबई (एजेंसी)। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के माता-पिता ने शनिवार को केंद्र सरकार आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे को हिरासत में लेने और भारी पुलिस



बल की तैनाती पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या छात्र चंबल के डाकू हैं। पुलिस ने राजधानी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अभिजीत दीपके, यूट्यूबर ध्रुव राठी और लगभग 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और जंतर-मंतर पहुंचने की उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। अभिजीत के पिता भगवान दीपके ने पत्रकारों से कहा, श्मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली में इतना पुलिस बल क्यों तैनात किया गया है? यह छात्रों का आंदोलन है। क्या चंबल के डाकू दिल्ली में जमा हुए हैं?

संस्थापक एवं संयोजक
यज्ञार्च्य संतोषा नन्द
महाराज

आप सभी देशवासियों को

दुर्गा पूजा

दुःसह

विजयदशमी दिवाली

का हार्दिक शुभकामनाएं

श्री ओम साहू दीपू

अरविन्द पाण्डेय
(पत्रकार)

हरि ओम साहू
वरिष्ठ समाज सेवी

सुरील कुमार यादव
पूर्व उपाध्यक्ष नगर निगम प्रयागराज

सर्वपितृ अमावस्या: संगम तट पर उमड़ी भीड़, तर्पण–पिंडदान कर पूर्वजों को किया नमन

प्रयागराज। पितृपक्ष के अंतिम दिन शनिवार १० अक्तूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर संगम तट सहित गंगा–यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान, तर्पण और पिंडदान कर अपने पूर्वजों का



स्मरण किया। पितृपक्ष के अंतिम दिन शनिवार १० अक्तूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर संगम तट सहित गंगा–यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान, तर्पण और पिंडदान कर अपने पूर्वजों का स्मरण किया। महालया अमावस्या के अवसर पर तीर्थ पुरोहितों के मार्गदर्शन में विधि–विधान से श्राद्ध कर्म किए गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन ज्ञात–अज्ञात सभी पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध किया। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि नौ अक्तूबर की रात ९रू३५ बजे से शुरू होकर १० अक्तूबर की रात ९रू१९ बजे तक रहेगी। श्राद्ध के लिए कुतुप मुहूर्त सुबह ११रू४५ से दोपहर १२रू३१ बजे तक, रौहिण मुहूर्त दोपहर १२रू३१ से १रू१८ बजे तक और अपराह्न काल १रू१८ से ३रू३७ बजे तक है। विशेष मुहूर्त में लोगों ने अपने पितरों का आह्वान कर उनको तर्पण किया। पिंडदान में परंपरा के अनुसार चावल या जौ के आटे, दूध, खोवा, काले तिल, घी, शहद और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। कुछ परंपराओं में पके चावल से भी पिंड बनाए जाते हैं। कुश, जल, गंगाजल, सफेद फूल और अक्षत का उपयोग तर्पण तथा पूजन में होता है। सामग्री और विधि में परिवार की परंपरा तथा तीर्थ पुरोहित के निर्देश के अनुसार अंतर हो सकता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या और महालया अमावस्या भी कहा जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है। मान्यता है कि इस दिन उन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध किया जा सकता है, जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है अथवा जिनका श्राद्ध निर्धारित तिथि पर नहीं हो पाया। इस दिन तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और सामर्थ्य के अनुसार दान करने की परंपरा है।

संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, कानूनी साक्ष्य का विकल्प नहीं बन सकता: कोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब ४१ साल पुराने हत्या और डकैती के प्रयास से जुड़े मामले की सुनवाई में विवेचना पर हेरानी जताई। कहा कि घटनास्थल के आंगन में दरवाजे के पास खून मिला था। जबकि, मृतक का शव चारपाई पर पाया गया। इसके बावजूद विवेचक ने यह पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि घायल को चारपाई तक कैसे और किन परिस्थितियों में लाया गया। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने जगनायक सिंह और संतोष की अपील स्वीकार कर ली। साथ ही उन्हें मिली सात–सात साल के कठोर कारावास की सजा का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, वह कानूनी साक्ष्य का विकल्प नहीं बन सकता। मामला बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के अलीना गांव का है। अभियोजन के अनुसार, २७ सितंबर १९८३ की रात दीनदयाल की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी धुरिया भी घायल हुई थीं। आरोप था कि जगनायक सिंह तमंचा, संतोष फारसा और रामराज लाठी लेकर घर में घुसे थे। लूटपाट के प्रयास का विरोध करने पर दीनदयाल की हत्या कर दी गई।बांदा के विशेष न्यायाधीश ने २५ जनवरी १९८५ को तीनों को घर में घुस कर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए सात–सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

पुरुष उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह व महिला उपाध्यक्ष पर अन्नपूर्णा सिंह पहले स्थान पर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वार्षिक चुनाव में शुक्रवार को पुरुष और महिला उपाध्यक्ष पदों के मतों की गिनती पूरी हो गई। पुरुष उपाध्यक्ष के चार पदों पर हुई मतगणना में शक्ति सिंह १६७९ वोट के साथ सबसे आगे रहे। वहीं, महिला उपाध्यक्ष के दो पदों पर अन्नपूर्णा सिंह (४०५५ वोट) और रंजना सिंह (३०४९ वोट) ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसएफए नकवी व चुनाव अधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि पुरुष उपाध्यक्ष के चार पदों और महिला उपाध्यक्ष के दो पदों के कुल १०,०३१ मतपत्रों की गिनती पूरी हुई। पुरुष उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह, आशुतोष पांडेय (१३४७ वोट), अनवीश कुमार श्रीवास्तव (१२१५ वोट) और जितेंद्र सिंह (११७० वोट) क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। दोपहर दो बजे के बाद कार्यकारिणी सदस्य के १० पदों के लिए गिनती शुरू हुई। इसमें २०० मतपत्रों की गणना की गई। चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी, राजकुमार शुक्ला, अनुभव शुक्ला ने बताया कि शनिवार को पितृ विसर्जन होने के कारण मतगणना स्थगित रहेगी। अब कार्यकारिणी सदस्य के १० पदों के लिए मतपत्रों की गिनती ११ नवंबर को सुबह १० बजे से शाम पांच बजे तक लाइब्रेरी हॉल में होगी।

क्लेमेंट टाउन व कंदरोरी पंजाब ने फाइनल में बनाई जगह

प्रयागराज। आर्मी पब्लिक स्कूल, न्यू कैंट में चल रही तीन दिवसीय एडब्ल्यूईएस बास्केटबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता (लड़कियों) का फाइनल मुकाबला शनिवार को होगा। यह प्रतियोगिता ८ अक्तूबर को शुरू हुई थी। शुक्रवार को लीग व सेमीफाइनल मैचों के बाद दो टीमों ने फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल मुकाबला आर्मी स्कूल, क्लेमेंट टाउन और आर्मी स्कूल, कंदरोरी पंजाब के बीच खेला जाएगा। शुक्रवार को हुए सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले देखने को मिले। पहले सेमीफाइनल में क्लेमेंट टाउन ने खड़की पुणे को १८–१६ अंकों से हराया। यह एक कांटे की टक्कर थी। दूसरे सेमीफाइनल में कंदरोरी पंजाब ने हिसार हरियाणा को ४५–२७ अंकों के बड़े अंतर से मात दी। इन परिणामों के आधार पर क्लेमेंट टाउन और कंदरोरी पंजाब फाइनल में पहुंचे। शुक्रवार को हुए लीग मैचों में भी रोमांचक भिड़ंत हुई। पांचवें लीग मैच में आर्मी पब्लिक स्कूल, क्लेमेंट टाउन ने हिसार हरियाणा को २६–२१ अंकों से पराजित किया। छठे मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल, खड़की पुणे ने कोलकाता को ४०–२१ अंकों से हराया। प्रतियोगिता के दौरान एसओ स्कूल लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन राव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। विद्यालय की प्राचार्य नीना शंकर ने भी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

महाराष्ट्र में शिवसेना नेता की हत्या कर प्रयागराज में छिपे थे दो आरोपी, एसटीएफ ने दबोचा

प्रयागराज। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णकर की हत्या के बाद फरार हुए दो आरोपियों को प्रयागराज में गिरफ्तार किया गया है।

महाराष्ट्र पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नैनी के अरैल सेल्फी प्वाइंट के पास से दोनों को पकड़ा। आरोप है कि चुनावी रंजिश में नेता की गोली मारकर हत्या की गई थी। वारदात के बाद दोनों आरोपी महाराष्ट्र से भागकर प्रयागराज में छिपे थे।

महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णकर की गोली मारकर हत्या के मामले में वांछित दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को नैनी के अरैल सेल्फी प्वाइंट के पास से पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र निवासी संतोष कनौजिया और अमित सिंह के रूप में हुई है। वारदात के बाद दोनों महाराष्ट्र से भागकर प्रयागराज आ गए थे।

एसटीएफ के मुताबिक, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कापुरबावड़ी थाने में दर्ज हत्या के मामले में संतोष कनौजिया

और अमित सिंह वांछित थे।

महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ से सहयोग मांगा था। इसके बाद एसटीएफ की



प्रयागराज इकाई ने आरोपियों की तलाश शुरू की।

एसीपी शैलेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण और प्रभारी जय प्रकाश राय के नेतृत्व में गठित टीम ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ शुक्रवार रात करीब ७रू३० बजे नैनी स्थित अरैल सेल्फी प्वाइंट के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टीम में उपनिरीक्षक विनय तिवारी, मो. हबीब अहमद सिद्दीकी, मुख्य आरक्षी पंकज तिवारी और आरक्षी चालक अखंड प्रताप पांडेय शामिल रहे।

चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप

एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि २९ सितंबर २०२६ को ठाणे के

चितलसर—मानपाड़ा क्षेत्र

में चुनावी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था।

पुलिस के अनुसार, ब्लॉक प्रमुख /कॉरपोरेटर के चुनाव



को लेकर पुरानी रंजिश थी। आरोप है कि प्रदीप पूर्णकर को तमंचे से गोली मारने के साथ चापड़ से गर्दन पर वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई।

इस मामले में कापुरबावड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसटीएफ के मुताबिक, मामले में तीन अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि संतोष कनौजिया और अमित सिंह फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों महाराष्ट्र से निकलकर प्रयागराज आ गए थे। संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संतोष के खिलाफ पहले भी

७० ट्रेनें रद्द: हमसफर, राजधानी समेत कई निरस्त, मोबाइल पर आने लगा निरस्तीकरण का मैसेज

प्रयागराज। ट्रेनों को निरस्त किया गया उसमें वीआईपी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, शिवगंगा, पटना राजधानी, सियालदाह राजधानी आदि ट्रेनें प्रमुख रूप से शामिल रहें। ट्रेनों के निरस्तीकरण के

इस निर्णय से संगमनगरी के हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। इस दौरान रेलवे प्रशासन को रिफंड के रूप में यात्रियों को बड़ी रकम चुकानी पड़ी। बिगड़ी यात्रियों की योजनाएं प्रयागराज के यात्रियों के लिए झटके की बात यह है कि

प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। अचानक ट्रेनों के रद्द होने से उन हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी पहले से बुकिंग थी और जो अपनी यात्रा के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे या तैयारी कर चुके थे। एकाएकट्रेनें बंद होने से यात्रियों की आगे की

प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। अचानक ट्रेनों के रद्द होने से उन हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी पहले से बुकिंग थी और जो अपनी यात्रा के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे या तैयारी कर चुके थे। एकाएकट्रेनें बंद होने से यात्रियों की आगे की

कोहड़ाघाट में १०.२० लाख के जेवर और नकदी चोरी

प्रयागराज। मेजा थाना क्षेत्र के बैरहना गांव में शुक्रवार को एक बंद मकान से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी हो गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राजेश्वर प्रसाद तिवारी के घर के सदस्य सुबह ९ बजे आवश्यक कार्य से बाहर गए थे। घर में कोई न होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश किया। उन्होंने कमरों में रखी अलमारियों के लॉक तोड़कर लगभग १० लाख रुपये मूल्य के गहने और २० हजार रुपये नकदी चुरा ली। राजेश्वर प्रसाद तिवारी की सास कुसुम कली के लौटने पर चोरी का पता चला। गृहस्वामी ने मेजा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की है और जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है।

२० वर्षों से तार की बाट जोह रहे खंभे



कर रहे हैं। वहीं बनवारी मौर्या, बाबूलाल मौर्या और दुःखी शर्मा समेत १५–१७ उपभोक्ता १५० से २०० मीटर दूर से तार खींचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार लंबी दूरी से खींचे गए तारों के कारण आए। दिन बिजली आपूर्ति बाधित होती है।

योजनाएं पूरी तरह बिगड़ गई हैं।

दरअसल, गुरुवार को दिल्ली में भीषण सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के कारण लगभग ५,००० यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए थे और



उनकी ट्रेनें छूट गई थीं। इस बीच दस अक्तूबर को सीजेपी एवं कुछ अन्य संगठनों की ओर से दिल्ली में बड़े आंदोलन की घोषणा के चलते रेलवे प्रशासन १० अक्तूबर की सुबह ४रू०० बजे से दोपहर २रू०० बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचने वाली कई प्रमुख मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और ईएम्यू/मेम्ू ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशनों से ही

दर्ज हैं एफआईआर

एसटीएफ के अनुसार, संतोष कनौजिया के खिलाफ पहले भी दो एफआईआर दर्ज हैं।

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को नैनी थाने में दाखिल कराया गया। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), प्रयागराज की अदालत में पेश कर ट्रॉजिट रिमांड की प्रक्रिया शुरू की, ताकि उन्हें महाराष्ट्र ले जाकर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।

गोली मारने के बाद चापर से किया था वार

महाराष्ट्र के ठाणे में २९ सितंबर २०२६ की रात करीब नौ से ११ बजे के बीच की हत्या की गई थी। मनोरमा नगर और मानपाड़ा इलाके में स्थित उनके कार्यालय के बाहर हुए हमले में हेलमेट और मास्क पहने बाइक सवार बदमाश शामिल थे। आरोपियों ने कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और धारदार हथियार चोंपर से भी हमला किया। गंभीर रूप से घायल को कापुरबावड़ी स्थित इन्फिनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, वारदात के पीछे चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश की बात सामने आई थी।

रद्द कर दिया गया है। दोपहर बाद यात्रियों के मोबाइल में ट्रैन निरस्तीकरण के मैसेज भी आने लगे। जंतर–मंतर पर प्रदर्शन को लेकर प्रयागराज में अलर्ट, बढ़ी सुरक्षा

दिल्ली के जंतर–मंतर पर शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस भी अलर्ट हो गई है। शहर के पत्थर गिरजाघर के समीप धरनास्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। धरनास्थल से सुभाष चौराहे तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही रेलवे स्टेशनों और रोडवेज बस अड्डे के आसपास भी निगरानी बढ़ाई गई है। जुलाई में हुए प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए पुलिस इस बार किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती। कॉंक्रोच जनता पार्टी के आह्वान पर जुलाई में प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पर धरना–प्रदर्शन हुआ था।

दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार किए बिना मृत्युदंड उचित नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दोषियों के सुधार की संभावना पर विचार किए बिना मृत्युदंड देना उचित नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर दो लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो आरोपियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने विवेचना और पुलिस रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए डीजीपी उत्तर प्रदेश को जांच कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने बारीक और शाहबाद की ओर से दायर अपील पर दिया है। मुजफ्फरनगर के छप्पर थाने में नवंबर २०११ को हत्या का प्रयास, हत्या व अन्य मामले में एफआईआर याचियों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि क्षेत्र के बरला गांव में दो पक्षों के बीच खेत की मेड़ और पेड़ों को लेकर विवाद हुआ अभियोजन के अनुसार हमले में आजाद उर्फ राजा और रियास उर्फ मुखिया की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में वर्ष २०१७ को आरोपियेों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। याचियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामला जघन्य होने के बावजूद इसे दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। घटना जमीन विवाद से उत्पत्ती थी। साथ ही दोषियों के सुधरने की संभावना और अन्य परिस्थितियों पर विचार किए बिना मृत्युदंड दिया गया था। इसलिए मौत की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने प्राथमिकी के समय में बदलाव, पंचायतनामा में काट–छांट और हथियारों की बरामदगी में खामियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। इसके साथ ही डीजीपी को मुजफ्फरनगर के एसएसपी से समन्वय कर जिले से बाहर के एसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने तथा तीन महीने में कार्रवाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

ओबीसी जातियों के पिछड़ेपन के आकलन में जुटे आयोग से हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की विभिन्न जातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गठित आयोग के कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि आगरा जिले में तीन लाख से अधिक ओबीसी आबादी के मुकाबले आयोग के सामने केवल १७९ लोग पहुंचे, जबकि इनमें से भी सिर्फ २९ लोगों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने आयोग से अब तक किए गए कार्यों और पिछड़ेपन के आकलन की प्रक्रिया का ब्योरा तलब किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दशरथ यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों और स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। सुनवाई के दौरान आयोग के अधिकता ने बताया कि प्रदेश के ४० जिलों में आंकड़े जुटाने का ६० प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष जिलों में भी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने और प्रश्नावलियां जारी करने के बावजूद आयोग के सामने अपेक्षा से काफी कम लोग पहुंचे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग करीब पांच महीने से आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में लगा है लेकिन उसके गठन के बाद बांदा जिले गई सलाहकार समिति की अब तक आयोग के साथ कोई बैठक नहीं हुई है। समिति की पहली बैठक १२ अक्तूबर को प्रस्तावित है। खंडपीठ ने सवाल किया कि छह महीने की निर्धारित समयसीमा में पूरे प्रदेश का काम कैसे पूरा किया जाएगा। कोर्ट ने आयोग से स्पष्ट करने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डॉ. के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ और सुरेश महाजन बनाम प्रदेश राज्य के फैसलों में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के तहत जातिवार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के अनुभवजन्य आंकड़े किस तरह जुटाए जा रहे हैं और उनका आकलन कैसे किया जाएगा। कोर्ट ने आगरा जिले में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण सीलबंद लिफाफे में १४ अक्तूबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई १४ अक्तूबर को दोपहर १२ बजे होगी।

कैंसर पीड़ित नौनिहाल को खून चढ़ाने के लिए वसूले नौ हजार, कोर्ट खफा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्लड कैंसर से जूझ रहे दो माह के बच्चे को खून चढ़ाने के लिए नौ हजार रुपये वसूलने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने निजी अस्पताल को आयुष्मान योजना से भी बाहर करने के राज्य सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने मुरादाबाद के सर्जिमेड हॉस्पिटल की याचिका पर दिया है। मामले के अनुसार, अस्पताल को १८ जून २०२६ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कार्रवाई के आदेश में कहा गया कि बच्चे को खून चढ़ाने की प्रक्रिया का विवरण इलाज करने वाले डॉक्टर ने बेड हेड टिकट में दर्ज नहीं किया था। गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती मरीज के उपचार के दौरान यह विवरण दर्ज करना अनिवार्य था। अस्पताल की ओर से समिति के समक्ष पेश हुए डॉक्टर ने भी प्रक्रियागत चूक स्वीकार की थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य पैनल समिति के आदेश में भले ही कारणों का विस्तार से उल्लेख नहीं था, लेकिन इससे रिकॉर्ड पर सामने आए तथ्यों का महत्व कम नहीं हो जाता। उपलब्ध सामग्री से योजना लागू करने और उसके तहत उपचार के दौरान जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करने में अस्पताल की ओर से गंभीर कमियां प्रथम दृष्ट्या सामने आई हैं।

६२ दिन से ५५ एकड़ धान की फसल डूबी

प्रयागराज। अमिलिया कला (नहवाई) में ६२ दिन से ५५ एकड़ धान की फसल पानी में डूबी हुई है। बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था न होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की गेहूं की बुवाई भी प्रभावित होनी तय है। पिछले वर्ष भी बारिश पर सामने आ पानी न निकल पाने से किसान गेहूं की बुवाई नहीं कर पाए थे। सात अगस्त को हुई बारिश से अमिलिया कला में धान की फसल पूरी तरह डूब गई थी। शिकायत के बाद भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी। फसल नष्ट हो गई और समस्या जस की तस बनी हुई है। किसान विमलेश पाण्डेय ने बताया कि दो वर्ष से गेहूं की बुवाई नहीं हो पा रही है। दिलीप शुक्ला के अनुसार, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से हर वर्ष धान डूबता है।

विन्ध्यवासिनी प्रसाद पांडेय ने बताया कि उनकी व्यक्तिगत कुल २० बीघे धान की फसल डूबी है। बारिश के पानी से दो वर्ष से धान की फसल डूब रही है। गेहूं की बुवाई भी प्रभावित होती है। शिकायत के बाद भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गोसौरा खुर्द में भी धान की फसल डूबी हुई है। एसडीएम अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि पानी निकासी की व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

सम्पादकीय.....

फार्मा कंपनियों के तोहफे

लंबे समय से यह बात सार्वजनिक विमर्श में रही है कि मरीजों के हितों पर कुठाराघात करके, फार्मा कंपनियां उपहार देकर चंद डॉक्टरों व अस्पतालों को साध रही हैं। फॉर्मा कंपनियां हजारों करोड़ रुपये का बजट डॉक्टरों को खुश करने के लिये रखती हैं ताकि उनके उत्पाद खरीदने के लिये मरीजों को बाध्य किया जा सके। विडंबना यह है कि सरकारें सब–कुछ जानते–बूझते हुए भी खामोश बैठी रहती हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को अब निर्देश देना पड़ा है कि वह फार्मा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग पर अविलंब रोक लगाए। बाकायदा, डॉक्टरों को खुश करने के लिये, तोहफे देने वाली फार्मा कंपनियों पर लगाम लगाने के लिये विशेषज्ञ कमेटी बनायी जाए। निश्चय ही इस अपवित्र गठजोड़ को नियामक तंत्र के दायरे में लाने की दिशा में यह एक स्वागत योग्य कदम होगा। निर्विवाद रूप से यह एक हकीकत है कि आर्थिक प्रलोभन या कीमती तोहफे मरीजों को दिए जाने वाले दवाइयों के परामर्श को प्रभावित करते हैं। फार्मा कंपनियों के इशारे पर लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन का असर मरीजों और उनकी उपचार लागत पर पड़ता है। इस अनैतिक प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दिशा में अदालत की पहल वक्त की जरूरत है। अदालत में वादी द्वारा दायर याचिका में इस बात पर बल दिया गया था कि फार्मा कंपनियां चुनिंदा दवाइयों की बिक्री बढ़ाने के लिये चिकित्सकों को महंगे तोहफे, विदेश यात्राएं आदि अन्य प्रकार के लाभ पहुंचाती हैं। निश्चित रूप से ऐसी अनैतिक परंपराएं जहां एक ओर क्लिनिकल फैसलों पर प्रभाव डाल सकती हैं, वहीं जरूरत से ज्यादा दवा लिखने की गलत प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दे सकती हैं। दरअसल, रोगों से जूझ रहा मरीज या तिमारदार आमतौर पर यह निर्णय नहीं ले पाते कि कोई दवा कितनी जरूरी है या नहीं है। यह भी कि किसी दवा का बाजार में अन्य सस्ता विकल्प मौजूद है कि नहीं। लेकिन इस प्रलोभन नीति के चलते फार्मा कंपनियां अपना उल्लू सीधा करने में कामयाब हो जाती हैं। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि देश में इस अनैतिक परिपाटी पर अंकुश लगाने के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। पहले से ही यूनिकॉर्म कोड फॉर फार्मास्प्टिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसिज–2024 के तहत डॉक्टरों को फार्मा कंपनियों से किसी भी प्रकार के तोहफे लेने, देश–विदेश की महंगी यात्राओं की सुविधाएं पाने या किसी भी तरह से आर्थिक लाभ लेने पर रोक लगाई गई है। बाकायदा इस बाबत शिकायत आने पर उसके निपटारे के लिये भी व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि शिकायतों के निपटारे के लिये एथिक्स कमेटी, खर्चों की जानकारी देने और शीर्ष पैनल सिस्टम भी मौजूद हैं। वह बात अलग है कि नियामक संस्थाएं यदा–कदा ही जागती हैं। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण सवाल को माना है कि क्या फार्मा कंपनियों को किसी कानूनी नियम–कायदे के दायरे में लाया जाना चाहिए? पुराने अनुभव तो यही बताते हैं कि स्वेच्छा से नियमों का पालन करना एक व्यावहारिक विकल्प नहीं हो पाता है। उपभोक्ताओं व मरीजों में जागरूकता के अभाव में ऐसे मामले होने के बावजूद बहुत कम शिकायतें सामने आती हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि फार्मा कंपनियों का खेल जारी नहीं है। दरअसल,कम शिकायतें सामने आने की अन्य कई वजहें हैं। मसलन, डॉक्टरों को महंगे उपहार या आर्थिक लाभ के मामलों की कम रिपोर्टिंग का होना, नियमों का ठीक प्रकार से लागू न हो पाना या फिर ताकतवर फॉर्मा लॉबी का सामना करने में हिचकिचाहट की वजह से शिकायतें कम नजर आती हैं। उल्लेखनीय है कि पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कानून के जरिये इसे कानूनी आधार देने की कोशिशों पर अधिकार क्षेत्र और इसकी कानूनी वैधता को लेकर प्रश्न उठे थे। ऐसे में फिर जरूरी हो जाता है कि प्रस्तावित कमेटी को अफसरशाही की लेट–लतीफी से बचाया जाए। कमेटी को वैश्विक बाजार मॉडल, हितों के टकराव, जानकारी उजागर करने की जरूरत, ऐसे मामलों मे सजा, स्वतंत्र जांच और मेडिकल रेगुलेटर की भूमिका की जांच करनी चाहिए। सही मायने में सरकार को एक स्पष्ट कानूनी रोडमैप तैयार करना चाहिए, जिससे किसी नये कानून की जरूरत का पता चल सके।

एक ही मुद्दे पर दो समानांतर मोर्चे

एजेन्सी
चुनाव चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आंदोलन गुरुवार को और तेज हो गया। मंगलवार और बुधवार के बाद गुरुवार को भी इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद फिर से एकत्र हुए। मल्लिकार्जुन खड्गे ने एक बार फिर सभी सांसदों और कांग्रेस नेताओं को लंच पर बुलाया। इस बार कर्नाट प्लेस के मोएट्स में सारा इंडिया ब्लॉक एकत्र हुआ तो अमित शाह ने पुलिस और सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा वहीं रेस्तरां के बाहर लगाव दिया। निर्वाचित सांसदों का एक जगह जमा होना और साथ खाना खाना क्या किसी खतरे का संकेत है, जिससे निपटने के लिए पुलिस बुला ली गई। अभी ठंड का मौसम आते ही कोई सांसद मक्के की रोटी और साग की दावत अपने घर पर रखेगा, कोई मकर सक्रांति पर दही–चूड़ा के लिए साथी सांसदों को न्यौता देगा, तो क्या इन सभी के बंगलों के बाहर पुलिस तैनात होगी। क्योंकि अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब मोदी–शाह का उड़ इतना बढ़ चुका है कि जहां इंडिया के सांसदों को देखा वहीं पुलिस

तैनात करवा दी। यह डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि चुनावों में धांधली करने के लिए एसआईआर का जो पूरा कुचक्र चलाया गया है, उसकी सच्चाई सामने आ रही है। विपक्ष के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने का वक्त चाहते हैं, जो उन्हें नहीं मिल रहा और इस बात पर विरोध करने की इजाजत भी नहीं मिल रही। गुरुवार को एक बार फिर तमाम विपक्षी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में राजघाट की तरफ बढ़े और इन पंक्तियों के लिखे जाने तक एक बार फिर उन्हें रोकने की कोशिशें जारी हैं। राजघाट पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगा दी गई है, यानी भीड़ जमा होने से रोकने का ऐलान हो गया है। निर्वाचित सांसदों को जब भीड़ कहा जाने लगे तो यह समझना कठिन नहीं है कि लोकतंत्र की क्या गत बनाई जा रही है। वैसे जिस तरह से मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उठी आवाज को दबाने के लिए दमनकारी तरीके अपनाए हैं, उस पर गुरुवार को कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया। के सी वेणुगोपाल ने सात तारीख को ही राज्य,

जिला और ब्लॉकमंडल की कांग्रेस इकाइयों को पत्र लिखकर कहा था कि जो सलूक मल्लिकार्जुन खड्गे, राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों के साथ किया गया, उसके विरोध के लिए आठ अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाए। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर तो लगातार हलचल देखने मिलती है, लेकिन जिला और मंडल स्तर की इकाइयों में स्थानीय नेताओं की सक्रियता से पार्टी मजबूत दिखती है। बीते 12 सालों में देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता इसी वजह से हतोत्साहित थे कि उन्हें दिशा देने वाले नेता संगठन पर ध्यान नहीं देते थे। कई जगहों पर कांग्रेस इसी वजह से मजबूत नहीं हो पाई क्योंकि आपसी गुटबाजी रही। बीच में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड्गे ने इस कमजोरी को दूर करने के लिए लगातार राज्य इकाइयों के साथ बैठकें की, संगठन को नए सिरे से मजबूत बनाने के लिए 2025 में काफी फैंसले भी लिए गए। लेकिन उनका उतना असर नहीं हुआ, जितना अब हो रहा है। क्योंकि कार्यकर्ता भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ–साथ समूचा विपक्ष सड़क

पर उतर आया है। यह संघर्ष चुनावों में हार की निराशा को दूर करने में असरकारी साबित हो रहा है। हालांकि इस संघर्ष का नतीजा क्या निकलेगा, यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक ही मुद्दे यानी एसआईआर में गड़बड़ी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर दो समानांतर आंदोलन चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने भी 10 अक्टूबर को जंतर–मंतर पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इससे पहले आठ अक्टूबर को बंगलुरु में उसने प्रदर्शन किया। जिसमें अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज और उनके साथ जर्मनी से आए यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल हुए। अब ये सभी लोग 10 अक्टूबर को भी जंतर–मंतर पर रहेंगे। वामपंथी छात्र संगठन नेहा बोरा ने भी 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए सभी से जुटने का आह्वान किया है। अभी 2 अक्टूबर को ही योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, मनोज झा आदि के साथ भी नेहा बोरा ने वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

जुलाई में पेपर लीक के खिलाफ भी ऐसे ही दो अलग–अलग मोर्चे खोले गए थे। राहुल गांधी तो छात्रों की गूंज कर ही रहे हैं, उधर सीजेपी ने भी आंदोलन किया था। हालांकि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो दोनों को ही सफलता मिली। लेकिन इस आंदोलन में भी नेहा बोरा मंच के नीचे अनशनरत थीं।

और उन्हें राहुल गांधी ने खास तौर पर बुलाकर मुलाकात की थी, न्याय के लिए संघर्ष में साथ देने का वादा किया था। मगर अब नेहा बोरा ने वोट चोरी के खिलाफ 10 तारीख को तो एकजुट होने की बात कही, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो मोर्चा खोला है, जिस तरह रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें उन्होंने साथ आने क्यों नहीं कहा, यह विचारणीय है। छह तारीख को नेहा ने एक पोस्ट भी लिखी कि कुछ जन–प्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, जबकि दूसरे अपने दिन गिनने में लगे हैं…इस पोस्ट के साथ राहुल गांधी का वीडियो उन्होंने लगाया है जिसमें पुलिस उन्हें जबरन पकड़ कर ले जा रही है। नेहा अगर इसमें कुछ जनप्रतिनिधि की जगह सीधे राहुल गांधी का नाम लिखती तो उनकी पोस्ट का महत्व कुछ कम नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब भी राहुल गांधी को निर्विवाद नेता मानने में कोई हिचक दिखाई जा रही है, या कोई इश्रक है, जो ऐसा करने से रोक रही है। राहुल गांधी या इंडिया का मौजूदा संघर्ष किसने नेहा बोरा, ध्रुव राठी, प्रकाश राज या अभिजित दिपके के प्रमाणपत्र या समर्थन का मोहताज नहीं है। इंडिया के निर्वाचित सांसदों ने जिस तरह सड़क की लड़ाई छेड़ी है, वह सराहनीय है। लेकिन सवाल यही है कि जब मंजिल एक ही है तो फिर सिविल सोसायटी खुलकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के साथ क्यों नहीं आ रही। क्या उसने जो समानांतर मोर्चा खोला है, उसका उद्देश्य यही है कि आंदोलन होता तो दिखे लेकिन परिणाम वही आए जो मौजूदा सत्ता के हक में है। आखिर ये तमाम लोग इतने मासूम तो नहीं हैं कि इन्हें बंट कर लड़ने और मिल कर लड़ने का फर्क ही न पता हो।

वोटर के अधिकार की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी

राजेश पांडेय

भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हर किसी के निशाने पर हैं। उन्हें हटाने की मांग और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया रद्द करने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर की गई है। उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा कराने के लिए मजबूर करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस की अनुआई में विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बहस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति, चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त और विधि विशेषज्ञ आगे आए हैं। केवल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। उसके पास आयोग के बचाव में ठोस और कारगर दलीलें नहीं हैं। फिर भी, उसके कई प्रवक्ता सक्रिय रहते हैं। समझ से परे है कि चुनाव आयुक्त पर संदेह जताने और सवाल उठाने का बचाव भाजपा की तरफ से क्यों होता है। भाजपा का बचाव चुनाव आयोग की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। संदेह पैदा होता है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है। वैसे भी, सरकार ने

आयोग को अपनी शर्तों पर चलाने और मनमानी की खुली छूट देने के कानूनी प्रावधान किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा संविधान और कानून की मंशा को खिलाफ काम करने का मामला इतना जोर नहीं पकड़ता यदि दो चुनाव आयुक्तों बीएस संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों का इंडियन एक्सप्रेस की खबर में खुलासा नहीं होता। दोनों आयुक्तों ने दस माह में 14 बार मुख्य चुनाव आयुक्त के एकतरफा आदेशों पर लिखित एतराज जाहिर किया था। आयोग ने भारी विरोध के बीच एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की। उसने बिहार, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव निपटने का इंतजार नहीं किया। उस समय कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिए थे कि चुनावों के बाद एसआईआर कराई जा सकती है। लेकिन आयोग को तो करोड़ों वोटरों को मतदाता सूचियों से बाहर करने की जल्दी थी। एसआईआर की प्रक्रिया ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खबरें बताती हैं कि इससे 13 करोड़ से अधिक वोटर मतदाता सूचियों से बाहर हो चुके हैं या बाहर होने की कगार पर हैं। इसमें मृत, किसी स्थान पर जा चुके वोटर शामिल हैं। मताधिकार के साथ देश का भविष्य जुड़ा है। लोकतंत्र में जनता अपने पसंद की सरकार वोट चुनती है। इतने लोगों का मताधिकार खत्म होना मामूली बात नहीं है। इससे चुनाव

आयोग की विश्वसनीयता पर संदेह स्वाभाविक है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुयन ने मामले से जुड़े मुद्दों का गहराई से विश्लेषण किया है।जस्टिस भुयन ने 4 अक्टूबर को एक व्याख्यान में कहा, शकौं भी ऐसी प्रक्रिया जो भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करती है और उन्हें बिना मतदान का नागरिक बनाती है, वह संविधान का उल्लंघन होगी। किसी भी तरह के टालमटोल या अन्य तर्कों से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भारतीय नागरिक से वोट देने का अधिकार छीनना, उसके शरीर से आत्मा निकालने के समान होगा। यह संविधान की मूल भावना पर आघात हैच। उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए अपने सहयोगी जज के कथन पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन ने जस्टिस भुयन की बात को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने एक अन्य व्याख्यान में कहा कि आपके पास ऐसा चुनाव आयोग नहीं हो सकता जो इस तरह काम करे या जिसका कामकाज इतना खराब हो। वे सवाल उठाते हैं, मतदाताओं को इतने बड़े पैमाने पर बाहर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई। पश्चिम बंगाल चुनावों

में 90 लाख वोटरों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यह हैरान करने वाला आंकड़ा है। वे जोर देते हैं, 90 लाख वोटरों का मताधिकार से वंचित होना भी सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगाने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व और एक वर्तमान न्यायाधीश की चिंता चुनाव आयोग की कार्यशैली के खिलाफ व्याप्त बेचोनी और असंतोष की झलक दिखाती हैं। वैसे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने किसी का नाम लिए बिना कहा है कि शि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी अन्य कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज को उन मामलों में नहीं बोलना चाहिए जो किसी कोर्ट के सामने पेंडिंग हैंर। जस्टिस गवई ने एसआईआर में हुई धांधली पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं समझी है। यहां एक बात का जिक्र कर सकते हैं। पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है कि कुछ साल पहले जस्टिस गवई ने जज लोया की मौत के मामले में उस वक्त टिप्पणी की थी जब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। न्यायाधीशों का देश, समाज,संविधान, कानून के शासन से जुड़े मुद्दों पर बोलना नई बात नहीं है। अलबत्ता, 2014 के बाद खुली अभिव्यक्ति में कमी आई थी। डर का माहौल लोगों को बोलने

से रोकता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद लोगों ने पहले के समान खुलकर बोलना शुरू किया है। मीडिया का एक हिस्सा भी बेरोकटोक आवाज उठाने लगा है। वहीं सरकार की भक्ति और विपक्ष के खिलाफ मुद्दे खोजने में जुटे शगोदी मीडियाश के स्वर फिलहाल थोड़े मंद पड़े हैं। बहरहाल, मताधिकार के मूल मुद्दे पर लौटते हैं।

चुनाव आयोग का मूल काम स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और वोटरों का अधिकार सुनिश्चित करना रहा है। इधर, वह अपनी मूल भूमिका से भटक कर वोटरों को निकालने की मुहिम में लगा है। एसआईआर में लोगों के सामने कदम–कदम पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। नए वोटरों का पंजीयन करने वाले फार्म 6 में पूछा गया कि क्या वे, उनके माता–पिता, दादा–दादी 2002 की पिछली एसआईआर के समय मतदाता सूचियों में शामिल थे। यह अनिवार्य शर्त कितनी कठिन है। सवाल है, कितने वोटर ऐसी शर्त पूरी कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रुकावटों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने आयोग के हर फैसले पर मुहर लगाई। चुनाव आयोग अब भी कह रहा है कि उसने फार्म–6 में कोई बदलाव नहीं किए हैं। सिर्फ एक घोषणा जोड़ी है। उसे भी हटा लिया है। आयोग कोई भी सफाई दे

भारत का चुनावी संकट अब ले रहा सर्वोच्च न्यायालय की परीक्षा

के रवींद्रन

भारत की चुनाव प्रणाली अब ऐसी स्थिति में पहुंच गयी है जहां बहस सिर्फमतदाता सूची में गलतियों तक सीमित नहीं है। ज्यादा अहम सवाल यह है कि क्या नागरिक उस संवैधानिक संस्था पर भरोसा बनाए रख सकते हैं, जिसे यह तय करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सूची में कौन शामिल होगा, नाम कैसे हटाए जाएंगे और क्या इस प्रक्रिया के नियम निष्पक्ष रूप से लागू किए जा रहे हैं? चुनाव आयोग के दावों के बावजूद, भारतीय की जनता के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप ज्यादा विश्वसनीय लग रहे हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े घटनाक्रमों ने इस विवाद को महज एक आम पक्षपाती शिकायत मानकर खारिज करना मुश्किल बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मई में फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बिहार में एसआईआर करने का अधिकार है। इसलिए, यह फैसला इस बात का समर्थन नहीं करता कि एसआईआर अपने आप में असंवैधानिक है। लेकिन असली मुद्दा अब इस बात पर आ गया है कि उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया गया, नाम हटाने को लेकर क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए, और क्या आयोग के फैसले एक बहु–सदस्यीय संवैधानिक संस्था के लिए जरूरी सामूहिक प्रक्रिया के जरिए लिए गए थे? एसआईआर के साथ–साथ एक और अनसुलझा संस्थागत मुद्दा भी चल रहा है। सर्वोच्च

न्यायालय की एक बेंच ने गत सितंबर माह में बंटा हुआ फैसला सुनाया था कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामलों को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। उस कानून ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया, जिससे चयन करने वालों में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और नामित मंत्री शामिल हो गए। मामला अगले प्रक्रियात्मक कदम के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। कुल मिलाकर, ये विवाद चुनावी वैधता के तीन चरणों से जुड़े हैं, रेफरी की नियुक्ति कौन करता है, रेफरी फैसले कैसे लेते हैं और जिनकी देखरेख में चुनाव हो रहा है, उसमें कौन हिस्सा ले सकता है। सड़कों पर इसके राजनीतिक नतीजे पहले ही दिखने लगे हैं। युवाओं के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध–प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जबकि विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और छात्र समूह प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया और आगे और लामबंदी की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग उन आरोपों को खारिज करता है कि उसके कार्यों का उद्देश्य सत्ताधारी भाजपा को लाभ पहुंचाना था, जबकि प्रदर्शनकारी और विपक्षी दल ठीक ऐसे ही पक्षपाती परिणामों का आरोप लगाते हैं। उन विरोध प्रदर्शनों को आरोपों के सबूत के तौर

पर नहीं देखा जाना चाहिए। न ही जन आक्रोश को संवैधानिक फैसले का विकल्प माना जाना चाहिए। उनका महत्व कहीं और हैरू वे दिखाते हैं कि क्या होता है जब प्रशासनिक प्रक्रिया पर बहस लोकतांत्रिक वैधता के विवाद में बदल जाती है। संवैधानिक प्रणाली में अभी भी ऐसे रास्ते हैं जिनसे विवाद को सुलझाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड मांग सकता है, जांच कर सकता है कि क्या कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, आयोग के भीतर असहमति के कानूनी महत्व को निर्धारित कर सकता है, पात्र मतदाताओं को गलत तरीके से बाहर किए जाने से बचा सकता है और उल्लंघन साबित होने पर उपाय बता सकता है। इनमें से किसी के लिए भी न्यायालय को संविधान को फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा के कठोर अनुप्रयोग की आवश्यकता है जिनके लिए संविधान को बनाया गया था। अधिक खतरा तब पैदा होगा जब आधिकारिक जवाब आने से पहले ही आम संवैधानिक उपायों पर जनता का भरोसा खत्म हो जाए। एक बार जब नागरिक यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि चुनाव चुनावी प्रशासन में विफलताओं को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव कराने वाली मशीनरी ही विश्वसनीय जांच से परे है, तो विवाद गोल–गोल घूमने लगता है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब बहस को सुलझा नहीं सकती क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की वैधता ही बहस का विषय है। भारत उस बिंदु पर नहीं पहुंचा है जहां बड़े पैमाने पर विद्रोह ही

एकमात्र विकल्प हो। अदालतें काम कर रही हैं, याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, चुनाव आयोग आलोचना का जवाब दे रहा है और शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बना हुआ है। इसलिए, संवैधानिक उपायों के खत्म हो जाने की घोषणा करना तथ्यों से आगे की बात होगी। लेकिन मौजूदा टकराव में छिपी चेतावनी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। चुनावी लोकतंत्र आखिरकार कानूनों, मशीनों या मतदाता डेटाबेस की तुलना में अधिक नाजुक चीज पर टिका होता है। यह इस विश्वास पर टिका होता है कि हारने वाले को लगता है कि मुकाबला ईमानदारी से आयोजित किया गया था और मतदाता को लगता है कि भाग लेने का अधिकार किसी अपारदर्शी प्रक्रिया से गायब नहीं हो सकता। वह भरोसा अब असामान्य दबाव में है। इसे बहाल करने के लिए चुनौती का सामना कर रही संस्था के आश्वासनों और उसके राजनीतिक विरोधियों के आरोपों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए स्वतंत्र जांच में टिकने वाले तथ्यों और राजनीतिक विभाजन के पार अधिकार रखने वाले संवैधानिक जवाबों की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय अब उस स्थिति में है जहां से वे जवाब सबसे विश्वसनीय रूप से सामने आ सकते हैं। जरूरी बात यह नहीं है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष से बचाया जाए, बल्कि यह है कि मतदाता सूची को लेकर होने वाले विवाद को इस बात के झगड़े में बदलने से रोका जाए कि क्या लोकतांत्रिक रेफरी पर अब भी भरोसा किया जा सकता है?

प्रतिभा रांटा

मेरे शहर की कई जगहों के नाम आज भी ब्रिटिश भाषा में, मेरी फैमिली से कोई दिल्ली से आगे तक नहीं आया

टीवी और OTT के बाद लापता लेडीज से देश–विदेश दोनों जगहों से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली प्रतिभा रांटा इन दिनों खबरों में है निखिल अडवानी निर्देशित वेब सीरीज श्रेवल्‍यूशनरीजश् की वजह से। उन्होंने कहा— असल में हमारे परिवार से कोई दिल्ली से आगे तक नहीं आया था। परिवार के कड़े विरोध के बावजूद शिमला से मुंबई एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आई प्रतिभा रांटा ने आखिरकार टीवी और व्ज के बाद लापता लेडीज से देश–विदेश दोनों जगह ख्याति प्राप्त की, जब उनकी फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई थी। बीते दिनों ओटीटी की ही मूवी श्‍क्यूण्डश् में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए सराही गई प्रतिभा इन दिनों सबसे बड़ा फ्रीडम थाश् अपने करियर के विभिन्‍न पड़ावों के बारे में प्रतिभा बताती हैं, श्में जब मुंबई आई मेरे लिए वो सबसे बड़ा फ्रीडम था। यहां आने के लिए घरवालों को मनाना ही सबसे बड़ा पड़ाव था। असल में हमारे परिवार से कोई दिल्ली से आगे तक नहीं आया था। उसके बाद मुझे जितने भी मौके मिले, मैंने उसमें अपनी जान लगा दी। कॉलेज की पढाई के साथ मैंने ऑडिशन देने शुरू किए और उसी के जरिए मुझे अपना पहला शो कुर्बान मिला। लापता लेडीज जिसमें मेरे काम को खूब सराहा गया, वो भी मुझे ऑडिशन के बाद ही मिला था। फिर मेरी पिछली फिल्म अक्‍यूण्ड में भी मुझे पसंद किया गया। मैंने अपने करियर में जितने भी किरदार किए, वो मुझसे बिल्‍कुल अलग हैं और मुझे गर्व है कि मैं उन किरदारों को अदा कर पाई.श् सीरीज में क्रांतिकारी की भूमिका निभाने वाली प्रतिभा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, श्मुझे लगता है हमें सबसे पहले अपने अंदर क्रांति लानी होती है। अपने जीवन के फैसलों पर अधिकार रखने का साहस करना पड़ता है। मैंने तो अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं और फैसलों के लिए क्रांति की। जाहिर—सी बात है परिवार से कोई इस क्षेत्र में था ही नहीं, मगर फिर मेरे इरादों पर आगे चलकर उन्हें भी सपोर्ट करना पड़ा, जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया। आज मुझे इस बात पर गर्व है। अब देखिए न मेरे ग्रैंड पैरेंट्स 85 साल के हैं और वक्त के साथ मेरी दादी कमाल तरीके से इवॉल्व हुई हैं। आज मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर पाती हूं। आज मेरी दादी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है।श्लड़कियां जो करना चाहें, कर पाएंश् छोटे–बड़े परदे पर सशक्त किरदारों को निभाने वाली प्रतिभा महिला सशक्तिकरण को लेकर कहती हैं, श्लड़कियां जो भी करना चाहें और कर पाएं, तो वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एम्‍पावरमेंट होगा। हमें ऐसा लगता है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भी अनगिनत लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत है।श् उन्हें लड़की होने के नाते हीनता कब महसूस होती है? के सवाल पर वे कहती हैं, श्जहां तक हीनता की बात है, तो वो तो कभी भी, कहीं से भी महसूस हो सकती है। जब भी कोई लड़की अपनी बात रखती है या अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती है, तो उसे बहुत ही सोचप्रेरक होना पड़ता है, क्योंकि उसे तुरंत जज किया जाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं, जहां हमें लड़की होने के नाते हर कदम पर जद्दो–जहद करनी पड़ती है।श् शिमला जैसे अपने शहर में इतिहास के निशां खोजती हूंश् प्रतिभा का नया सीरीज 1857 के राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित है और प्रतिभा इसमें युवा क्रांतिकारी प्रतिभा लाहिड़ी का किरदार कर रही हैं। वे कहती हैं, श्जब भी आप इतिहास से जुड़ा कोई किरदार करते हैं, तब जरूरी होता है कि हम उनके संघर्ष को समझ पाएं औरउस किरदार के प्रति ईमानदार रहें। निखिल अडवानी (निर्देशक) और पूरी टीम ने गहन रिसर्च की, मगर साथ ही हमने इसे ड्रैमेटाईज भी किया, क्योंकि आखिरकार हमें दर्शकों का मनोरंजन भी करना है। ये भी कम संयोग और दिलचस्प बात नहीं कि मैं शिमला जैसे एक ऐसे



बॉलीवुड में जो नाम और शोहरत 90 के दशक की दिग्गज अदाकारा काजोल ने कमाई है, वैसा ही कुछ जलवा गुजरे दौर में उनकी मां तनुजा का भी हुआ करता था. तनुजा अपने दौर की सफल अभिनेत्री हुआ करती थीं जो आज अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. तनुजा ने हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज एक्टर्स संग स्क्रीन शेयर की हैं और अपने करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दीं. तनुजा अपनी फिल्मों और अदाकारी के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहे हैं. उन्होंने फिल्ममेकर से शादी की थी, हालांकि बहुत जल्द ही वो पति से अलग हो गई थीं. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी पति से तलाक नहीं लिया था. आइए आज आपको तनुजा के जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं. पिता डायरेक्टर तो मां थीं एक्ट्रेस तनुजा का ताल्लुक शुरु से ही फिल्मी दुनिया से रहा है. उनके पिता कुमारसेन समर्थ जाने–माने फिल्म निर्देशक थे, जबकि तनुजा की मां एक्ट्रेस थीं. उनका नाम शोभना समर्थ था. वहीं दिग्गज अदाकारा नूतन तनुजा की बड़ी बहन थीं. शोभना समर्थ और कुमारसेन के घर तनुजा का जन्म आजादी से पहले 23 सितंबर 1943 को मुंबई में

शहर से हूं, जहां का बिल्डिंग आर्किटेक्ट और बनावट ब्रिटिश और स्कॉटिश फील देता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे शहर का देश की आजादी की लड़ाई से गहरा रिश्ता रहा है। ब्रिटिश काल में 1864 से 1947 तक यह समर कैपिटल रहा, तो मैं जब भी शहर में घूमती थी, तो सोचती थी कि ब्रिटिश काल में यहां क्या हुआ होगा। मेरे शहर की कई जगहों के नाम आज भी ब्रिटिश भाषा के हैं। जब मैंने अपनी इस सीरीज के चार किरदारों रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, बाघा जतिन और मेरे किरदार के बारे में पढ़ा तो मैं भी उनके साहस से प्रभावित हुए बिना नहीं रही थी।श् हमें रोहित सराफ को अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर कड़ी मेहनत करते देखाश् अपने को—एक्टर रोहित सराफ के बारे में प्रतिभा बोलीं, श्रोहित सराफ बहुत ज्यादा मेहनती हैं। जब वे डायट पर होते थे, तो कुछ भी ऐसा नहीं खाते थे, जो उनकी डायट को खराब कर दे। मैंने उन्हें अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर कड़ी मेहनत करते देखा है। जहां तक काम की बात है, तो वे अपने किरदार में डूब जाते हैं।श्



धर्मेद्र की किस हरकत पर भड़क गई थीं तनुजा ?



हुआ था. जब काजोल की मां ने धर्मेद्र को जड़ा था थप्पड़, पति से अलग होने के बाद भी कभी नहीं लिया तलाक 7 साल की उम्र में किया था इस फिल्म में काम मां शोभना और पिता कुमारसेन के फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के चलते तनुजा ने बॉलीवुड में बतौर बाल कलाकार भी काम किया है. उन्हें सबसे पहले बड़े पर्दे पर फिल्म श्हमारी बेटीश् में देखा गया था. साल 1950 में आई इस फिल्म के वक्त तनुजा सिर्फ सात साल की थी. 1960 में बतौर एक्ट्रेस डेब्यू 1950 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू करने वाली तनुजा ने साल 1960 में लीड एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. 17 साल की उम्र में वो फिल्म श्छबीलीश् में नजर आई थीं. हालांकि उन्हें इंडस्ट्री में पहली बड़ी पहचान अगले साल यानी साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म श्हमारी याद आएगी।जब काजोल की मां ने धर्मेद्र को जड़ा था थप्पड़, पति से अलग होने के बाद भी कभी नहीं लिया तलाक डायरेक्टर शोमू मुखर्जी से की थी शादी तनुजा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 83 वर्षीय उनका नाम शोभना समर्थ था. वहीं दिग्गज अदाकारा नूतन तनुजा की बड़ी बहन थीं. शोभना समर्थ और कुमारसेन के घर तनुजा का जन्म आजादी से पहले 23 सितंबर 1943 को मुंबई में



विवेक ओबेरॉय ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग को एक नेगेटिव एक्टिविटी बताया और लोगों से इससे बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि ट्रोलिंग के बजाय लोगों को पॉजिटिव एक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए। दरअसल, बॉलीवुड क्रॉनिकल के साथ बातचीत के दौरान विवेक ओबेरॉय से पूछा गया कि सलमान खान ने ट्रोलिंग को लेकर बयान दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? इसके जवाब में विवेक ने कहा, “मुझे लगता है कि ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रोलिंग एक नेगेटिव चीज है। जिंदगी में करने के लिए इतने पॉजिटिव काम हैं, तो नेगेटिव चीजों में क्यों पड़े हो?” गौरतलब है कि सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच विवाद बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में गिना जाता है। दोनों के बीच तनाव की शुरुआत ऐश्वर्या राय से जुड़े रिश्ते को लेकर हुई थी। 2003 में विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान खान पर फोन करके धमकाने और परेशान करने के आरोप लगाए। विवेक के मुताबिक, सलमान ने उन्हें कई बार फोन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद काफी बढ़ गया और विवेक के मुताबिक उनके फिल्मी करियर पर भी इसका असर पड़ा। बाद के वर्षों में विवेक ने सलमान से माफी मांगने की कोशिश की। सलमान खान ने ट्रोलिंग पर नाराजगी जताई सलमान खान ने हाल ही में टीवी शो ‘बिग बॉस 20’ में सोशल मीडिया ट्रोलिंग, बॉडी–शेमिंग और एज–शेमिंग पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया आज गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार और पहचान का जरिया बन चुका है लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू ट्रोलिंग भी है।सलमान ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी को ट्रोल करने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि सामने वाला निजी तौर पर किन परिस्थितियों से गुजर रहा है।

नाना पाटेकर

जन्म

1 जनवरी, 1951

निधन

8 अक्टूबर, 2026

नाना पाटेकर की ये 5 फिल्में आज भी हैं लोगों की पसंद, हर किरदार में छोड़ी अपनी अलग छाप

बालीवुड के लीजेंड अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे, खबरों की मानें तो कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ नाना पाटेकर अपने सिंपल अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। इतने दिग्गज स्टार होने के बावजूद वह बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी जीते थे! उनकी कुछ फिल्में आज भी लोग वैसे ही देखना पसंद करते हैं जैसे पहले चलिए आपको उनकी बेस्ट 5 मूवीज बताते हैं जो लोगो को बहुत पसंद आई थी।

क्रांतिवीर (1994)

नाना पाटेकर ने इसमें प्रताप नारायण तिलक का किरदार निभाया था। गुस्सा, दर्द, बेबसी और देश के लिए लड़ने का जुनून इन सबको उन्होंने इतनी ताकत से पर्दे पर उतारा था।

गुलाम ए मुस्तफा

मुस्तफा के किरदार में नाना पाटेकर ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी निभाई जो अपराध की दुनिया में होने के बावजूद अपने अंदर इंसानियत और भावनाएं रखता है। गुलाम ए मुस्तफा नाना के उन किरदारों में से है जिन्हें आज भी लोग देखना पसंद करते हैं!

अग्निसाक्षी (1996)

इस फिल्म में नाना पाटेकर का किरदार काफी गंभीर और मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने एक ऐसे पति की भूमिका निभाई जिसके व्यवहार में प्यार के साथ–साथ जुनून और खतरनाक अधिाकार की भावना भी दिखाई देती है।

परिदा (1989)

अन्ना का किरदार नाना पाटेकर के करियर के सबसे प्रभावशाली किरदारों में माना जाता है। फिल्म में उनका खतरनाक और ठंडे मिजाज वाला किरदार बेहद असरदार रहा।

अब तक छप्पन (2004)

इसमें नाना ने साधु आगाशे नाम के पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। यह किरदार शांत, सख्त और अपने काम के प्रति जुनूनी है। नाना ने बिना जरूरत ज्यादा नाटकीयता के इस भूमिका को निभाया और अपने अभिनय से साधु आगाशे को यादगार बना दिया। नाना पाटेकर की खासियत यह रही कि उन्होंने सिर्फ हीरो बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिनमें गुस्सा, दर्द, डर, अपराध, इंसानियत और कमजोरी, सब कुछ दिखाई देता था। उनकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और चेहरे के भाव उनके किरदारों को और ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। वेलकम में उन्होंने कॉमेडी करके भी अपने फैंस को इंग्रेस किया। आपको नाना पाटेकर की कौन सी पिसउ सबसे अच्छी लगती है जिसे आप बार बार देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें...

आज मीडिया का सारा ध्यान ईविल डेड पर होगा, नाना पाटेकर पर मीटू का इल्जाम लगाने वाली तनुश्री दत्ता ने दिया शॉकिंग ब्यान

मशहूर एक्टर नाना पाटेकर के निधन के बाद एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने खबर सुनी थी लेकिन लखनऊ में अपने काम पर ध्यान देना चाहती थीं। उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदना भी जताई और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें, साथ ही इसे ईविल डेड भी कहा। उन्होंने कहा, मैंने खबर सुनी है। आज मेरा काम का दिन है। मैं एक इवेंट के लिए लखनऊ जा रही हूं और उसी पर ध्यान देना चाहती हूं। यह सब होने के लिए कितना अजीब दिन है क्योंकि मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही हूं। यह मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण था। मैंने पूरे दिन लाइव करने और कंटेंट पोस्ट करने की योजना बनाई थी और अब मुझे चिंता है कि शाम को मीडिया की दिलचस्पी सिर्फ ईविल डेड में होगी। इसलिए, जब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तब मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। तो, निश्चित रूप से, परिवार के प्रति संवेदना। बहुत–बहुत धन्यवाद। जानकारी के लिए बता दें कि तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर 2018 में भारत के मीटू मूवमेंट के दौरान एक विवाद के केंद्र में थे। एक्ट्रेस ने मशहूर एक्टर पर हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। नाना पाटेकर ने आरोपों से इनकार किया और उन्हें झूठा बताया। नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। उन्हें गोवा के डोना पाउला स्थित मणिपाल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उन्हें सुबह 4.20 बजे लाया गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि उन्होंने लगभग 45 मिनट से एक घंटे तक पीसीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टरों ने सुबह 5.20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।

गीली लकड़ी मत लगाना... नाना पाटेकर ने अपनी मौत के बारे में सालों पहले ही सोच लिया था

मराठी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले नाना अपनी मौत को लेकर भी बेहद बेबाक थे। साल 2023 में अपनी फिल्म द वैक्सीन वॉर के प्रचार के दौरान उन्होंने हंसते–हंसते अपनी मौत और अंतिम संस्कार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। सितंबर 2023 में दिए एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था कि वे मौत को जीवन का एक स्वाभाविक सच मानते हैं।और जानते हैं कि एक न एक दिन सबको जाना ही है।अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी का जिद्ध करते हुए उन्होंने बताया था, मैंने अपने लिए 12 मन सूखी लकड़ियां पहले से ही संभालकर रखी हैं।

शेफ रणवीर बरार ने शेयर की ढाबा स्टाइल जूसी चिकन पुलाव की रेसिपी, रोस्टेड वेजिटेबल चटनी के साथ लगेगा लाजवाब



○ **डिनर में कुछ स्पेशल खाने का दिल कर रहा लेकिन ज्यादा कुकिंग का मन नहीं है तो जूसी चिकन पुलाव की इस रेसिपी को जरूर नोट कर लें। शेफ रणवीर बरार ने रोस्टेड वेजिटेबल चटनी के साथ इस आसान सी रेसिपी को शेयर किया है।**

वीकडेज पर डिनर के लिए किसी बढ़िया सी डिश का ख्याल आ रहा। लेकिन बहुत सारी कुकिंग का मन नहीं तो घर बैठे बिल्कुल ढाबा स्टाइल चिकन पुलाव बनाकर तैयार कर लें। शेफ रणवीर बरार ने आसान सी विक् रेसिपी शेयर की है और साथ में रोस्टेड वेजिटेबल की चटनी जरूर बनाएं। जिसका स्वाद इस बासमती चावलों की खुशबू वाले चिकन पुलाव के साथ दोगुना हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लें इस मजेदार सी डिश बनाने की आसान सी रेसिपी।

जूसी चिकन पुलाव बनाने की सामग्री
एक किलो चिकन
एक चम्मच धनिया की डंठल बारीक कटी हुई
दो चम्मच लहसुन-अदरक का पेस्ट
नमक स्वादानुसार
दो चम्मच नींबू का रस
दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई
एक चम्मच सरसों का तेल
पुलाव के लिए
दो से तीन चम्मच तेल
दो से तीन चम्मच घी
एक चम्मच जीरा के दाने
दो बड़े साइज के प्याज स्लाइस में कटे हुए
दो सूखी कश्मीरी लाल मिर्च
एक चौथाई कप फ्राईड अनियन
एक इंच अदरक का टुकड़ा
दो हरी मिर्च
एक तेजपत्ता
ताजी हरी धनिया की पत्तियां
700 ग्राम बासमती राइस धोएं और 30 मिनट भीगे हुए नमक स्वादानुसार
बड़े आकार में कटे टमाटर
रोस्टेड वेजिटेबल चटनी की सामग्री
एक बड़ा टमाटर, एक बड़ा प्याज, एक बड़े साइज का शिमला मिर्च, एक चौथाई कप ताजी पुदीना की पत्तियां,आधा कप ताजी हरी धनिया की पत्तियां, दो हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, दो चम्मच दही

चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी
सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दें। चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन को किसी बड़े बर्तन में लें। इसमें धनिया की डंठल, लहसुन-अदरक का पेस्ट, नमक स्वादानुसार, नींबू का रस, हरी मिर्च, देगी मिर्च और सरसों का तेल डालकर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब सारे चिकन पर कोटिंग हो जाए तो इसे साइड में रख दें।

अब चिकन पुलाव बनाने की तैयारी करें। गैस पर बड़े आकार की हांडी चढ़ाएं और उसमें तेल और घी डालें।

गर्म होते ही तेल जीरा डालें और साथ में कटे हुए प्याज डाल दें।

दो से तीन मिनट तक प्याज को भूनें और जब प्याज ट्रांसपैरेंट दिखने लगे तो इसमें सूखी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। साथ ही मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर ढंक दें।

कुछ मिनट तक चिकन को पकने दें। फिर से ढक्कन खोलकर इसमें फ्राई अनियन डालें। साथ ही हरी मिर्च, तेज पत्ता,पुदीना और धनिया की कटी हुई पत्तियां ताजी डाल दें।

साथ में अच्छी तरह से धोएं और आधे घंटे भीगे बासमती चावल भी डाल दें।

धीरे हाथों से चलाएं और सबको मिक्स करें। अब बचे हुए धनिया के पत्तों को डालें। साथ में पानी और नमक डालकर मिक्स करें।

नींबू का रस निचोड़ें और जो नींबू बीज निकालकर काट रखे थे उन्हें भी डाल दें।

ढंककर उबाल आने दें।

जब इसमें एक से दो उबाल आ जाए तो कटे हुए टमाटर डालें और ढंककर करीब 15 से 18 मिनट तक पकाएं।

ध्यान रहे टाइम के साथ ही चिकन का ध्यान रखें, चिकन को पकने में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। जब चिकन पक जाए और चावल नर्म हो जाएं तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।

ढंककर छोड़ दें। बनाएं वेजिटेबल चटनी

अब वेजिटेबल चटनी बना लें। इसे बनाने के लिए टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज को दो से तीन टुकड़ों में काट लें।

फिर तवे पर थोड़ा सा तेल डालें और सारे टुकड़ों को पलट कर रखें और इन्हें रोस्ट कर लें। तेज फ्लेम पर रोस्ट करते वक्त कुछ हिस्सा जलता सा फील होगा लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ दें, इसी से चटनी का फ्लेवर होगा।

जब ये पक जाए तो चॉपिंग बोर्ड पर निकालकर सबके छिलके अलग कर दें।

मिक्सी के ग्राइंडर जार में सारी रोस्ट सब्जियां डालें। साथ ही धनिया की पत्तियां, हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, तेल, पुदीना की ताजी पत्तियां और दही डालकर ब्लेंड करें। बस स्मूद सी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी।



दवाई लेते समय हम आमतौर पर डोज और टाइमिंग का ध्यान रखते हैं, लेकिन यह देखना भूल जाते हैं कि उसके साथ कितना पानी पीना चाहिए। कई लोग

गोली सिर्फ दो-तीन घूंट पानी के साथ निगल लेते हैं या फिर दवाई लेते ही लेट जाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, ये छोटी-सी गलती खाने की नली में जलन और दूसरी परेशानी की वजह बन सकती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि दवाई के साथ जितना ज्यादा पानी पिएं, उतना बेहतर है। आखिर

एक गोली के साथ कितना पानी लेना सही है और दवाई लेते समय किन गलतियों से बचना चाहिए? जान लेते हैं-

एक गोली के साथ कितना पानी पिएं? आमतौर पर गोली या कैप्सूल को एक पूरे गिलास (200 से 250 मिलीलीटर) सादे पानी के साथ लेना बेहतर माना जाता है। सिर्फ दो-तीन घूंट पानी के साथ गोली निगलने से बचें। पर्याप्त पानी गोली को खाने की नली से आसानी से नीचे जाने में मदद करता है। इससे गोली के वहां अटकने या ज्यादा

देर तक चिपके रहने का खतरा कम होता है।

कम पानी के साथ दवाई लेने से क्या दिक्कत हो सकती है?

लिलावती अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. सी. सी. नायर के अनुसार, पर्याप्त पानी के बिना दवाई लेने पर गोली खाने की नली में चिपक सकती है। इससे जलन हो सकती है और दवाई को नीचे जाने या घुलने में भी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए गोली निगलते समय पानी की मात्रा को

चेहरे पर गुलाबी निखार चाहिए? रोज पीनी शुरू करें 3 चीजों से बनी ये ड्रिंक, फर्क साफ दिखेगा!

○ **चेहरे पर नेचुरल पिंक ग्लो चाहिए तो 3 चीजों से बनी ये नेचुरल ड्रिंक पीना शुरू करें। विलागिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये ड्रिंक स्किन को अंदर से ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में मदद करती है, साथ ही हाइड्रेशन को भी सपोर्ट करती है।**

ग्लोइंग और हेल्दी त्वचा के लिए बाहरी देखभाल के साथ-साथ डाइट और हाइड्रेशन पर ध्यान देना भी जरूरी है। ऐसे में अगर प्रॉपर स्किनकेयर

रूटीन फॉलो करने के बाद भी आपका चेहरा डल नजर आ रहा है तो ये होममेड ड्रिंक आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चुकंदर, सौंफ और तुलसी के पत्तों से बनी ये ड्रिंक विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर है। इससे चेहरे पर निखार आता है और हाइड्रेशन के कारण स्किन ज्यादा प्लंप और सॉफ्ट भी नजर आती है। अगर आप ग्लोइंग स्किन के लिए कोई सिंपल और इफेक्टिव नुस्खा ढूँढ रहे हैं तो ये ड्रिंक पीना शुरू कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के रेगुलर इस्तेमाल से आपको

अपने चेहरे पर असर साफ नजर आएगा। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है-

पिंक ग्लो ड्रिंक बनाने के लिए चाहिए ये चीजें
चुकंदर- 1ध छोटा सौंफ- आधा चम्मच तुलसी- 5-7 पत्ते पानी- 1 गिलास आधे नींबू का रस- ऑप्शनल ग्लोइंग स्किन के लिए ऐसे बनाएं ड्रिंक

चेहरे पर गुलाबी निखार चाहिए तो रोजाना ये ड्रिंक पीना शुरू करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक चुकंदर को छीलकर छोटी-छोटी स्लाइसेज में काट लें। अब एक पैन में पानी चढ़ाएं। इसमें सौंफ, चुकंदर के टुकड़े और ताजा

तुलसी के पत्ते धो कर डाल दें। इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अच्छी तरह उबलने दें।

जैसे ही पानी का रंग हल्का गुलाबी होने लगे और पानी में तुलसी और सौंफ की खुशबू आने लगे, तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें। इसे हल्का ठंडा होने दें, फिर एक गिलास में छान लें। स्वाद और एकस्ट्रा बेनेफिट्स के लिए आप इसमें आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। कोशिश करें कि ताजा बनाकर ही पीएं।

रोजाना कब पीनी है ये ड्रिंक?

ये ड्रिंक आप रोजाना सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इसे पीने के लगभग आधा या एक घंटे बाद ही नाश्ता करें। लेकिन अगर आपको पेट में एसिडिटी,



हमारे देश में चाय महज एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि लोगों की रोज की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। ज्यादातर लोगों का दिन भी एक कप चाय के साथ ही शुरू होता है। अक्सर अपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि हेल्दी रहना है तो चाय छोड़ना जरूरी है, पर जिन लोगों को चाय की आदत है उनके लिए ये नामुमुकिन सा हो जाता है। लेकिन क्या वाकई चाय हमारी सेहत के लिए इतनी नुकसानदायक है? इसपर फिटनेस कोच डॉ ज्योति श्रीवास्तव एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि चाय पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसे पीने के तरीके में बदलाव करना जरूरी है। अगर आप भी रोज चाय पीते हैं तो इन 3 गलतियों को दोहराने से बचें।

डेली चाय पीते हैं तो ना

करें ये 3 गलतियां गलती 1- बहुत ज्यादा गर्म चाय पीना

बहुत से लोगों को तेज गर्म चाय पीने का शौक होता है। जबतक वो चाय को सिप-सिप कर के ना पीएं, उन्हें मजा ही नहीं आता। हालांकि नियमित रूप से ये आदत आपके खाने की नली यानी एसोफेगस के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कोच बताती हैं कि 65°सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाले बहुत तेज गर्म पेय नियमित रूप से पीने पर फूड पाइप के कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है।

इसे आसान शब्दों में समझें तो जब बहुत तेज गर्म चाय बार-बार आपके फूड पाइप यानी भोजन की नली से गुजरती है, तो उसके अंदर की परत को बार-बार डैमेज और इरीटेशन हो सकती है। इसलिए चाय

बनने के तुरंत बाद उसे ना पीएं, बल्कि कुछ देर हल्का ठंडा होने का इंतजार करें।

गलती 2- खाली पेट या खाने के तुरंत बाद चाय पीना फिटनेस कोच बताती हैं कि चाय में टैनिन नाम के कंपाउंड मौजूद होते हैं। ये तत्व खाने से मिलने वाले आयरन को बॉडी में सही से एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इसलिए खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद चाय पीना अर्वाइड करना चाहिए। खासकर अगर आपका आयरन लेवल कम है तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीने से भी बचना चाहिए। इससे पेट में एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

गलती 3- प्लास्टिक की छलनी इस्तेमाल करना चाय को छानने के लिए

दवाई के साथ कितना पानी पिएं और लेने के तुरंत बाद क्या न करें? डॉक्टर से जानें

○ **दवाई लेते समय डोज और टाइमिंग का ध्यान तो सभी रखते हैं, लेकिन पानी कितना पीना है, इस पर कम ध्यान जाता है। बहुत कम या ज्यादा पानी लेने से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसपर डॉक्टर की सलाह जान लेते हैं।**

लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

दवाई लेते ही लेटना भी सही नहीं

सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं, दवाई लेने के बाद आपका तरीका भी मायने रखता है। गोली निगलते ही

बिस्तर पर लेट जाने की आदत से बचना चाहिए। ऐसा करने पर दवाई खाने की नली में ज्यादा देर तक रह सकती है।

सीके बिरला अस्पताल, दिल्ली, की डॉ. मनीषा अरोड़ा के अनुसार, दवाई लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक लेटने से बचना चाहिए। तुरंत लेटने पर रिफ्लक्स और खाने की नली में जलन की परेशानी हो सकती है।

क्या ज्यादा पानी पीना सही है?

कम पानी के साथ दवाई लेने से परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं

है कि गोली के साथ बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। खासकर जिन लोगों को किडनी या दिल से जुड़ी किसी परेशानी की वजह से पानी कम पीने की सलाह दी गई है, उन्हें अपनी तरफ से पानी की मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए।

दवाई लेते समय कितना पानी पीना सही है?

दवाई चाय या जूस के साथ...

कई लोग सुबह की चाय, कॉफी या जूस के साथ ही अपनी दवाई निगल लेते हैं। लेकिन ऐसा हर दवाई के साथ करना सही नहीं होता, इसलिए दवाई लेने के लिए सादा पानी सबसे आसान ऑप्शन है। जब तक डॉक्टर ने कोई अलग तरीका न बताया हो, गोली को सादे पानी के साथ लेना ही बेहतर है।

पानी बहुत ठंडा या गर्म होना जरूरी नहीं

दवाई लेने के लिए खास तौर पर बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कमरे के तापमान वाला सादा पानी काफी है। डॉ. मनीषा अरोड़ा का कहना है कि दवाई लेने के लिए सामान्य तापमान का या हल्का गुनगुना पानी लिया जा सकता है। बहुत ठंडे पानी के साथ दवाई लेने की जरूरत नहीं है।

दवाई लेते समय इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंरू

गोली को सिर्फ दो-तीन घूंट पानी के साथ न निगलें, एक पूरा गिलास सादा पानी लें।

दवाई लेते समय बैठें या खड़े रहें।

दवाई निगलते ही लेटने से बचें।

बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई को चाय, कॉफी या जूस के साथ न लें।



दर्द या किसी तरह की समस्या महसूस होती है तो इसे खाली पेट पीना अर्वाइड करें। ऐसी स्थिति में आप नाश्ते के बाद ये ड्रिंक ले सकते हैं।

स्किन के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है ये ड्रिंक? चुकंदर में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ओवरऑल स्किन हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इससे चेहरे की डलनेस कम

होती है।

स्किन पर एक हेल्दी निखार देखने को मिलता है।

ये ड्रिंक स्किन की हाइड्रेशन को सपोर्ट करती है, जो ये ड्रिंक पीना अर्वाइड करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं

या किसी बीमारी के लिए नियमित दवाई लेने वालों को

नियमित पीने से चेहरे पर गुलाबी निखार नजर आ सकता है।

किन लोगों को अर्वाइड

करनी चाहिए? अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, बीपी लो रहता है या चुकंदर खाने से एलर्जी या पेट से जुड़ी समस्या होती है, तो ये ड्रिंक पीना अर्वाइड करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं या किसी बीमारी के लिए नियमित दवाई लेने वालों को भी इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए।

रोज चाय पीते हैं तो ये 3 गलतियां बिल्कुल ना करें, कैंसर तक का हो सकता है रिस्क!

○ **टी लवर हैं तो चाय पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है। बस चाय पीने के तरीके में बदलाव करें। फिटनेस कोच ने 3 गलतियां शेयर की हैं, जो आपको चाय पीते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।**

प्लास्टिक की छलनी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

कोच कहती हैं कि बहुत तेज गर्म चाय को प्लास्टिक की छलनी में छानने से उसके छोटे-छोटे कण चाय में आ सकते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसका सिंपला

सा सॉल्यूशन है कि प्लास्टिक की छलनी को हटाकर स्टेनलेस स्टील की छलनी का इस्तेमाल करें।

ये छोटी-छोटी बातें भी ध्यान रखें

दिन में बहुत ज्यादा चाय पीना अर्वाइड करें। 1 से 2 कप तक सीमित रखना बेहतर है।

चाय में जरूरत से ज्यादा



सक्षिप्त



टाटा मोटर्स ने एनवी ग्रुप के अधिग्रहण की पेशकश बढ़ाकर 14.40 यूरो प्रति शेयर की

टाटा मोटर्स लिमिटेड ने इटली की ट्रक विनिर्माता कंपनी इवेको ग्रुप एनवी के अधिग्रहण के लिए पेशकश मूल्य 0.30 यूरो बढ़ाकर 14.40 यूरो प्रति शेयर कर दिया है। कंपनी ने यह कदम नियामकीय मंजूरियों में देरी के महेनजर उठाया है। टाटा मोटर्स ने 2025 में अपनी अनुषंगी कंपनी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड के माध्यम से इवेको के रक्षा कारोबार को छोड़कर उसके अन्य कारोबार के अधिग्रहण की योजना की घोषणा की थी। इस सौदे का मूल्य 3.8 अरब यूरो (करीब 38,240 करोड़ रुपये) आंका गया था। वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने इससे पहले इवेको के लिए 14.10 यूरो प्रति शेयर की पेशकश की थी। इस आधार पर सौदे का मूल्य 3.82 अरब यूरो था। टाटा मोटर्स ने सितंबर में इवेको के सभी बकाया साधारण शेयरों के अधिग्रहण के लिए नकद भुगतान वाली स्वैच्छिक निविदा पेशकश शुरू की थी। इस पेशकश को स्वीकार करने की अवधि सात सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर, 2026 तक रहेगी। इवेको ग्रुप के शेयरधारकों को संबंधित प्रस्तावों पर मतदान के लिए 16 अक्टूबर को होने वाली असाधारण आम बैठक में हिस्सा लेना है। इवेको के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से इस सौदे का समर्थन किया है। टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि पहले की पेशकश कीमत इवेको के उचित और पूर्ण मूल्यांकन को दर्शाती थी। हालांकि, आवश्यक पूर्व मंजूरियों की प्रक्रिया में शुरुआती अनुमान से अधिक समय लगने के कारण कंपनी ने पेशकश मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि संशोधित पेशकश मूल्य 17 जुलाई, 2025 को इवेको के शेयर भाव से 33.47 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सिंगापुर यात्रा: भारत-सिंगापुर संबंध होंगे और मजबूत ?

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति थारमन शनमुगरलम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यह बैठक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9 से 11 अक्तूबर तक सिंगापुर की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों से भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने वैश्विक आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। इसके साथ ही, जारी ऊर्जा संकट से निपटने के तरीकों पर भी बात हुई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने एक्स पर बताया कि उनकी वित्त मंत्री के साथ अच्छी बातचीत हुई। वित्त मंत्री ने भारत में हो रहे नए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने सिंगापुर के नेताओं को भारत में निवेश और सहयोग के नए अवसरों से भी अवगत कराया।

रिजर्व बैंक: आरबीआई ने बैंकों के लिए

सीआरआर की दैनिक सीमा 99 फीसदी की

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के दैनिक रखरखाव नियमों को सख्त कर दिया है। शुक्रवार को हुई घोषणा के अनुसार, अब बैंकों को निर्धारित सीआरआर का 99 फीसदी दैनिक रूप से बनाए रखना होगा। यह सीमा पहले 90 फीसदी थी। संशोधित नियम 16 अक्तूबर से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से लागू होंगे। इस बदलाव से बैंकों की किसी एक दिन अपने आरक्षित शेष को कम करने की क्षमता काफी घट जाएगी। आरबीआई ने सीआरआर के समग्र अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया है। इस कदम का उद्देश्य बैंकों के दैनिक नकदी प्रबंधन को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य आरक्षित आवश्यकताओं का अधिक निरंतर रखरखाव सुनिश्चित करना है। संशोधित नियम का प्रभाव बैंकों की नकदी स्थिति और उनके कोष प्रबंधन प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। जिन बैंकों का काम न्यूनतम आरक्षित सीमा के करीब होता है, उन्हें अपने दैनिक नकदी प्रबंधन में बदलाव करने पड़ सकते हैं। यह फैसला आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के 7 अक्तूबर के बयान के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष के बाकी हिस्से में बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

क्या है सीआरआर का नया नियम?

मोजूदा व्यवस्था में बैंकों को एक पखवाड़े के दौरान निर्धारित सीआरआर के बराबर औसत शेष रखना होता है। उन्हें किसी भी दिन इस आवश्यकता का कम से कम 90 फीसदी बनाए रखने की छूट थी। नए नियम के तहत, यह दैनिक सीमा बढ़ाकर 99 फीसदी कर दी गई है। इससे बैंकों को हर दिन लगभग पूरा सीआरआर बनाए रखना होगा। यह केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी बनाएगा।

बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति कैसी है?

अगस्त और सितंबर के दौरान मजबूत पूंजी प्रवाह के कारण बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ी थी। इसमें आरबीआई की विशेष विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक (एफसीएनआर-बी) जमा सुविधा से जुटाई गई रकम भी शामिल थी। हालांकि, हाल के सप्ताहों में अतिरिक्त नकदी में कमी आई है। यह कमी परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (सीआरआरआर) नीलामी और खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत बॉन्ड बिक्री के कारण हुई।

अगस्त में औसत दैनिक अतिरिक्त नकदी 5.9 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यह 3.92 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

खेल

आईपीएल 2027: अजिंक्य रहाणे भी इम्पैक्ट प्लेयर नियम के विरोध में उतरे, हटाने की मांग

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के विवादित इम्पैक्ट प्लेयरश नियम की आलोचना की है। रहाणे ने इस नियम को लीग से हटाने की वकालत भी की है। रहाणे उन कई क्रिकेटरों में शामिल हो गए हैं जो इस नियम की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नियम से भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर्स का विकास रुक रहा है और यह किसी काम का नहीं है।

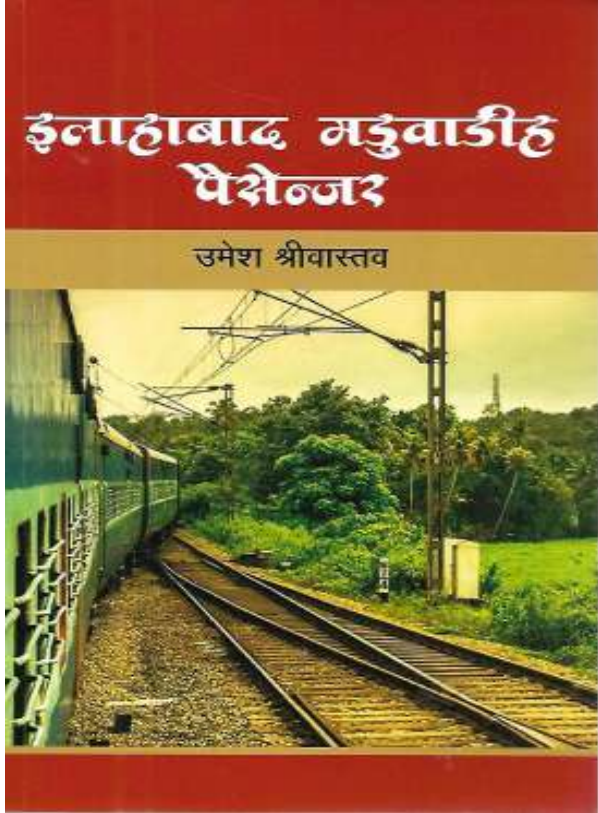
रहाणे बोले— ज्यादातर कप्तान इस नियम के थे खिलाफ

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके रहाणे ने कहा, मुझे लगता है कि इसे (इम्पैक्ट प्लेयर नियम) हटा दिया जाना चाहिए। मुझे याद है कि पिछले साल आईपीएल कप्तानों की बैठक से पहले, ज्यादातर कप्तानों

ने कहा था कि उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर नियम नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि यह नियम या गाइडलाइंस 2027 तक लागू हैं। इसलिए हमें नहीं पता कि वे इसे इस साल हटाएंगे या इस साल के बाद होने वाले बड़े ऑक्शन में हटाएंगे। हालांकि, असल में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम का कोई मतलब या फायदा नहीं है। रहाणे ने आगे कहा, यह नियम भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर्स के विकास में भी बाधा डाल रहा है, क्योंकि फ्रेंचाइजी बल्लेबाज की जगह गेंदबाज और गेंदबाज की जगह बल्लेबाज को लाकर बल्ले या गेंद से बेहतर नतीजा पाने की कोशिश करती हैं। भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या की कमी के कारण टीम को अक्सर उनके विकल्प की तलाश करनी पड़ती है। हालांकि, शिवम दुबे और नीतीश रेड्डी सामने आए हैं, लेकिन वे अभी भी हार्दिक की काबिलियत के स्तर तक नहीं

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल: शुरुआती दौर में मिले दोगुने से ज्यादा ऑर्डर

अमेजन इंडिया की 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026' सेल की शानदार शुरुआत हुई और पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस बार शुरुआती चरण में ऑर्डर किए गए उत्पादों की संख्या दोगुने से अधिक रही, जबकि उसके शॉपिंग मंच पर लोगों ने 44 करोड़ से अधिक बार 'विजिट' किया। ये आंकड़े देश के बड़े शहरों से बाहर भी ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती मांग और ग्राहकों के महंगे उत्पादों की ओर किए जा रहे रुख को दर्शाते हैं। अमेजन ने जारी बयान में कहा कि उसके मंच पर कुल 'विजिट' में से 72 प्रतिशत से अधिक ऐसे विजिटर थे जो भारत के शीर्ष नौ महानगरों के बाहर से थे। वहीं, पहली बार खरीदारी करने वाले ग्राहकों की संख्या में करीब 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शुरुआती रुझानों में स्मार्टफोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, सौंदर्य उत्पादों, घरेलू उपकरणों और रोजमर्रा के सामान की मजबूत मांग देखने को मिली। सेल की शुरुआत ऐसे समय हुई है, जब ऑनलाइन खुदरा कंपनियां त्योहारों के दौरान खरीदारी का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इसके लिए वे छूट, बैंक ऑफर, पुराने उत्पादों के बदले छूट और किस्तों में भुगतान जैसी सुविधाएं दे रही हैं।



समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।



पहुंच पाए हैं। इसके अलावा, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स तैयार होते नहीं दिख रहे हैं, खासकर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर्स, जो अब भारतीय क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऑलराउंडर तैयार करने पर

दिया जोर

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा, खासकर आईपीएल में ऑलराउंडर्स खेल से बाहर होते जा रहे हैं। मेरा पक्का मानना है कि आपको अपने ऑलराउंडर्स को तैयार करना चाहिए। भारतीय टीम के नजरिए से

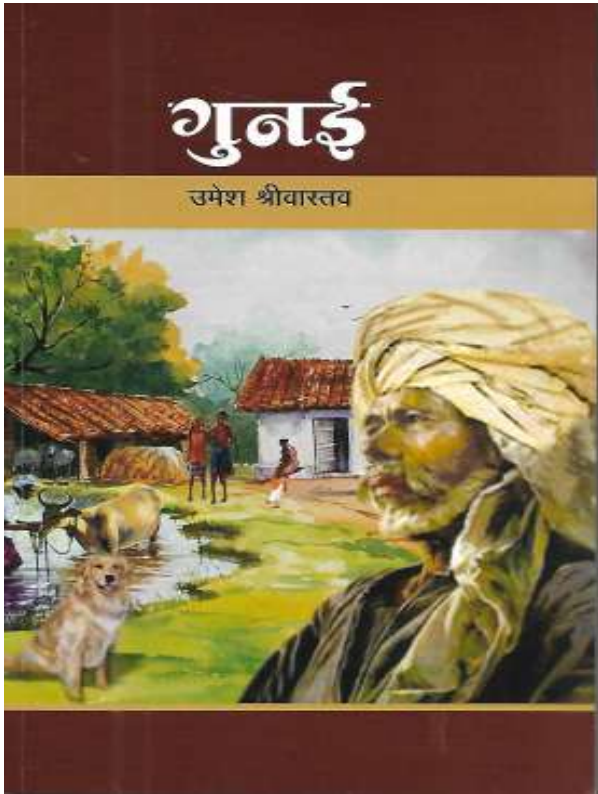
ऑलराउंडर्स बहुत जरूरी हैं। इसी कारण इम्पैक्ट प्लेयर नियम को हटा देना चाहिए। पिछले साल मैं किसी टीम का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ टीमें शायद 90/7 या 100/7 के स्कोर पर थीं और इस नियम के चलते एक अतिरिक्त

बल्लेबाज को उतारकर उन्होंने 200 रन तक बना लिए थे। यही कारण है कि मुझे लगता है कि गेंदबाजों को कुछ फायदा मिलना चाहिए और ऑलराउंडर्स भी खेल में पूरी तरह शामिल होने चाहिए। उन्हें इसे हटा देना चाहिए।

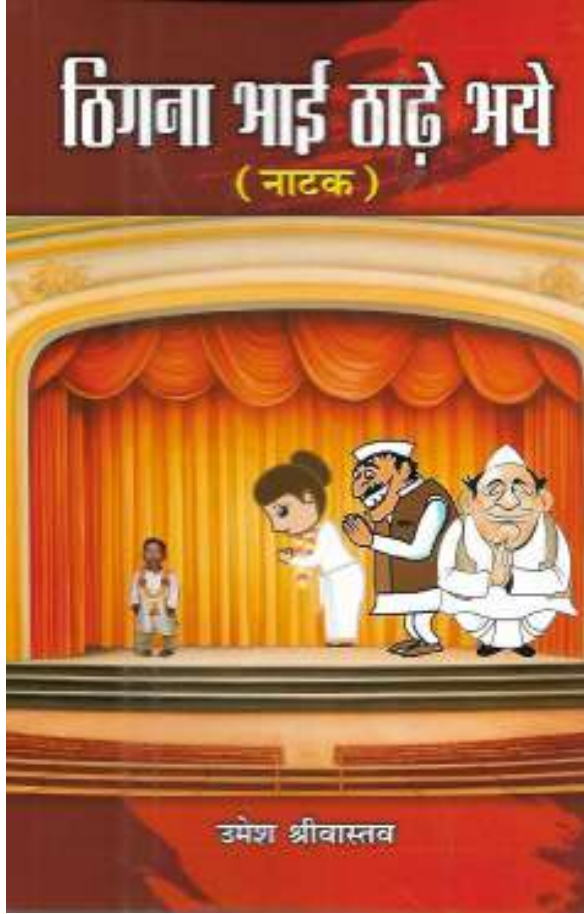
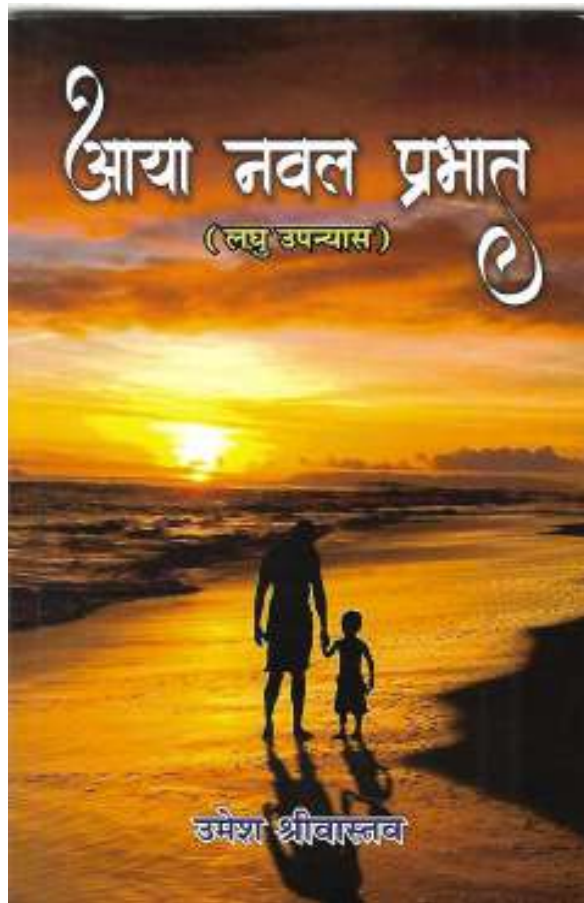
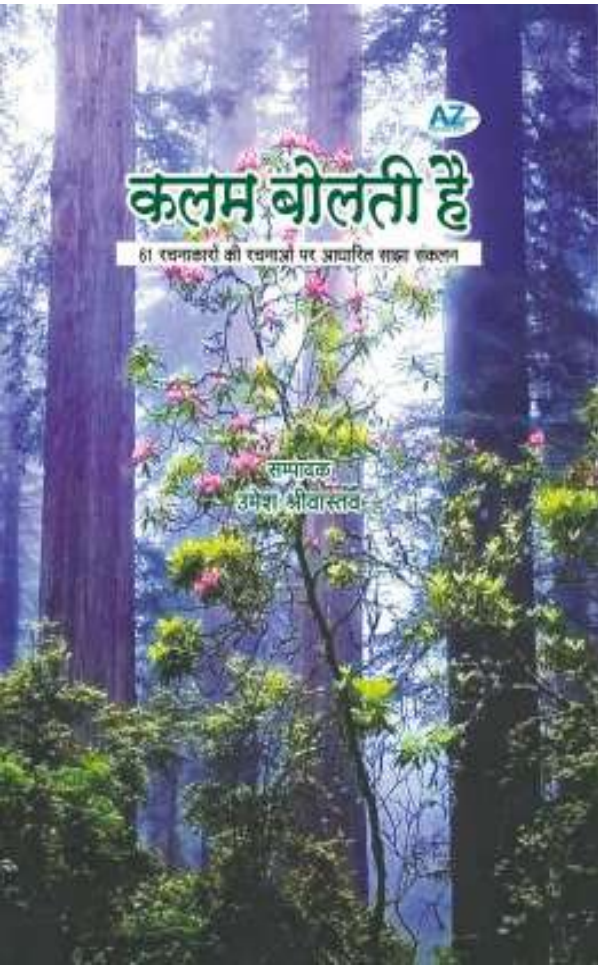
नैफेड-एफसीआई की पहल, आर्मी कैंटीन में मिलेगा भारत राइस

एमाएसएमई में एनपीए पर बोले सीईए नागेश्वरन

उपभोक्ताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) अब भारतीय सेना की कैंटीनों में भी अपने कदम जमाने जा रहा है। आने वाले दिनों में देश भर की सभी सैन्य कैंटीनों में भारत ब्रांड का चावल उपलब्ध होगा, जिसकी औपचारिक शुरुआत 12 अक्तूबर से होने की संभावना है। वर्तमान में नैफेड की ओर से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) को दालों की आपूर्ति की जा रही है। दालों की बेहतरीन गुणवत्ता को देखते हुए अब आर्मी ने नैफेड से चावल भी लेने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में नैफेड की ओर सेधसेना को सालाना करीब 35 हजार टन दालों की आपूर्ति की जा रही है, जबकि श्भारत राइसश की सालाना खपत



चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित



ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

अब चीन पर दूट पड़े बलूच लड़ाके, फूंक डाला कार्गो काफिला, मची तबाही!

पाकिस्तान में इन दिनों चारों तरफ ऐसा विद्रोह भड़का हुआ है उसे काबू पाने में शहबाज और मुनीर नाकाम दिख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत करने वाले विद्रोही अब तक तो मुनीर की सेना को ही ठोक रहे थे। लेकिन अब उन्होंने उस चीन को भी निशाने पर ले लिया है जो शहबाज मुनीर के साथ मिलकर उनके लड़ाकों को मार रहा था। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना के साथ ही अब चीन को भी भारी जख्म दे डाला है। पिछले कुछ समय के अंदर बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को मार डाला है। लेकिन अब चीन भी उनके टारगेट पर आ गया है। खबर है कि हथियारों से लैस बलूच विद्रोहियों ने ग्वादर पोर्ट की तरफ जा रहे एक बड़े कार्गो काफिलों को फूंक डाला है। यानी कि बलूचों ने अब चीन के हाथ भी जलाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारी गोलीबारी करते हुए बलूच

दक्षिण कोरिया: दाएगू शहर के सुपरमार्केट में छत गिरने से 38 लोग घायल, राष्ट्रपति ने दिए जांच के निर्देश

दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के दाएगू शहर से एक हादसे की खबर सामने आई है। शहर के एक सुपरमार्केट की प्लास्टर वाली छत का कुछ हिस्सा गिर गया। फायर अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 38 लोगों को मामूली चोटें आईं। दाएगू फायर डिपार्टमेंट ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि छत गिरने की घटना सुबह 10रु१6 बजे हुई। इसके बाद 66 अन्य लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद नौ लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया। फायर डिपार्टमेंट की अधिकारी यूं जोंग-मी ने बताया कि हादसे में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं, मौके पर मौजूद आपातकालीन कर्मियों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने की संभावना बहुत कम है।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा? घटनास्थल की एक तस्वीर में आपातकालीन बचावकर्मी चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर छत गिरने के बाद मलबे में खोजबीन करते हुए दिखाई दिए। हालांकि, अभी तक छत गिरने के कारण का तुरंत पता नहीं चल सका। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को लोगों को बचाने और घटना पर पूरी तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर नॉर्वे पर साधा निशाना, 8 युद्ध रुकवाने का किया दावा

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किए जाने को लेकर नॉर्वे पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि उन्होंने जितने युद्ध रुकवाए हैं, उसके हिसाब से उन्हें आठ बार नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। ट्रंप ने शुक्रवार को सिरैक्यूज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी दावा किया कि उन्होंने परमाणु शक्ति संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान को युद्ध में उलझने से रोककर करोड़ों लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने कहा, “आपके राष्ट्रपति के रूप में मैंने जिस अमेरिका का नेतृत्व किया, उसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह नॉर्वे और इतना अपमानजनक तथा शर्मनाक फैसला लेने वालों के माथे पर कभी न मिटने वाला कलंक है।” अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, “कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों के एक समूह ने नोबेल शांति पुरस्कार को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया है। ये लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं और वास्तव में सभ्यता के दुश्मन हैं। नॉर्वे, हम यह नहीं भूलेंगे कि आपने हमें यह पुरस्कार नहीं दिया।” इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और दक्षिण अफ्रीकी मूल की नवनेथम ‘नवी’ पिल्लई को प्रदान किया गया है। ट्रंप ने पिल्लई के बारे में कहा कि वह ऐसी शख्सियत हैं, “जिनके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं है।” ट्रंप ने कहा, “आज (शुक्रवार) संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाली एक उदारवादी महिला को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, जिनके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना। मैंने भी उनके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन फिर भी उन्हें बधाई।” इसके बाद ट्रंप ने उन युद्धों की सूची गिनाई, जिन्हें सुलझाने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि वह दो और संघर्षों— ईरान तथा रूस—यूक्रेन युद्ध— को समाप्त कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा, “नॉर्वे, हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने इतिहास में हमारे इतने अच्छे रिक्तों के बावजूद हमें यह पुरस्कार नहीं दिया। हमने आठ युद्ध रुकवाए। हमें हर युद्ध के लिए एक नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, यानी कुल आठ पुरस्कार।

आवश्यकता है
उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/ शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
 सम्पर्क सूत्र शहर समता हिन्दी दैनिक / साप्ताहिक समाचार पत्र मोबाईल नम्बर_9190052 39332 919450482227

विदेश

अब चीन पर दूट पड़े बलूच लड़ाके, फूंक डाला कार्गो काफिला, मची तबाही!



इतनी भयानक थी कि ग्वादर बंदरगाह के लिए भेजा जा रहा कीमती सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीबीसी की रीड माने जाने वाले गदर प्रोजेक्ट पर बलूच विद्रोहियों का खौफ किस तरह हावी है और अब पाकिस्तान के

यूएन में भारतीय नारी शक्ति: सांसद ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, प्रिया सरोज बोलीं- अपराध पर जीरो टॉलरेंस

यूएन। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत की दो महिला सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों पर देश का पक्ष रखा। महिमा कुमारी मेवाड़ ने जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बयान का जवाब दिया, जबकि प्रिया सरोज ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और मिशन पर तैनात विशेषज्ञों के आपराधिक आचरण और जवाबदेही का मुद्दा उठाया। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दोनों सांसदों के बयानों की जानकारी साझा की।

महिमा कुमारी ने पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाए?

संयुक्त राष्ट्र की चौथी समिति में उपनिवेशवाद से जुड़े मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान के जवाब में महिमा कुमारी ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर को लेकर झूठ और गलत जानकारी



महिमा कुमारी मेवाड़ सांसद

प्रिया सरोज सांसद

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

महिमा कुमारी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगियों ने अपने बुनियादी अधिकारों आजादी और

जम्मू-कश्मीर पर भारत ने क्या दोहराया?

मौके पर नहीं पहुंचाद्य जब तक सुरक्षा बल पहुंचे तब तक हमलावर द्वाइवर को अगवा कर आराम से फरार हो चुके थे। दरअसल ग्वादर पोर्ट केवल पाकिस्तान का एक साधारण बंदरगाह नहीं है बल्कि चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे अहम दिल माना जाता है। अरब सागर के तट पर बसा यह गर्म पानी का गहरा बंदरगाह पारस की खाड़ी के मुहाने पर और स्टेट ऑफ फॉर्मूज के ठीक बाहर स्थित है। जहां से दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। ग्वादर पोर्ट का मालिकाना हक भले ही पाकिस्तान सरकार के पास हो लेकिन इसका प्रबंध और संचालन पूरी तरह से चीनी कंपनी चाइनीज ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के हाथों में है। पाकिस्तान सरकार और चीन पर आरोप लगते आए हैं कि वो

बलूच से तेल, गैस और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं और बदले में स्थानीय बलूच लोगों को केवल गरीबी, बेरोजगारी और सैन्य दमन मिला है। यह वजह है कि बलूच विद्रोही ग्वादर से जुड़ी हर सड़क, हर काफिले और वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। नया हमला इस बात का साफ—सा संकेत है कि बलूच उग्रवादीयों ने अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। वो केवल सुरक्षा बलों की चौकियों पर ही हमले नहीं कर रहे। बल्कि ग्वादर को पूरे पाकिस्तान से जोड़ने वाले ख्संगीत, आर्थिक और व्यापारिक रास्ते को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि जब ग्वादर जाने वाले सामान से लदे ट्रेलरों को इस तरह सरेआम फूँका जाएगा और द्वाइवरों का अपहरण किया जाएगा तो कोई भी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी या द्वाइवर इस रूट पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।

यूएन में भारतीय नारी शक्ति: सांसद ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, प्रिया सरोज बोलीं- अपराध पर जीरो टॉलरेंस

पर भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और मिशन पर तैनात विशेषज्ञों की आपराधिक जवाबदेही से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि भारत कर्मचारियों के आपराधिक आचरण और कदाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। उन्होंने जवाबदेही तय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों के बीच मजबूत सहयोग तथा प्रभावी व्यवस्था बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा पर क्या कहा?

प्रिया सरोज ने कहा कि जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन और पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता मजबूत करने, सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और

जवाबदेही सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

निर्वाचित नेताओं को जेल में डालने, धार्मिक कट्टरपंथ और सरकारी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उपदेश देने से बचने की सलाह दी। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा।

प्रिया सरोज ने संयुक्त राष्ट्र में क्रौन—सा मुद्दा उठाया?

प्रिया सरोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की छठी समिति में एजेंडा आइटम 75

इससे पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि हसन को श्फायरिंग रस्वाड के जरिए मौत की सजा दी जाएगी और वह इसका हकदार है। ट्रंप ने हसन को र्शनकीर्ष बताया था। ट्रंप लंबे समय से मौत की सजा के खुले समर्थक रहे हैं। हालांकि, उन्होंने पेंटागन की उस योजना का जिक्र नहीं किया, जिसके तहत सजा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों को भी सजा की कार्रवाई दिखाना है। अमेरिका फोर्ट हुड गोलीबारी कांड में दोषी सेना के पूर्व अधिकारी मेजर निदाल हसन को सार्वजनिक तौर पर सजा—ए—मौत देगा। जहां उसने 13 सैनिकों की हत्या की थी, वहीं उसको गोली मारी जाएगी। करीब एक सदी बाद अमेरिका में सार्वजनिक तौर पर सजा देने का पहला मामला होगा। यही नहीं, अमेरिकी इतिहास में पहला मौका होगा जब मौत की सजा को टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि सजा का सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि लोग सबक ले सकें।

यूएन में पाकिस्तान को भारत की दो दूक, परमाणु धमकी के आगे कभी नहीं झुकेंगे

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि परमाणु हथियारों को शासन चलाने का “सामान्य साधन नहीं माना जाना” चाहिए। भारत ने कहा कि वह किसी भी परमाणु धमकी या दबाव के आगे नहीं झुकेगा। निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार करने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में शुक्रवार को भारत ने अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए जिनैवा स्थित भारत के स्थायी मिशन में वरिष्ठ सलाहकार (निरस्त्रीकरण) अनमोल शेर सिंह बेदी ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने कहा, “हम भारत के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने और उन्हें वापस सौंपने का आह्वान करते हैं।” बेदी ने साथ ही कहा कि भारत संघर्ष नहीं चाहता। उन्होंने कहा, “भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहा है और सभी के साथ शांति चाहता है। हालांकि, अगर गैर—जिम्मेदाराना कार्रवाइयों के लिए जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तो संकटों के बीच शांति केवल एक संक्षिप्त विराम बनकर रह जाएगी।” बेदी ने स्पष्ट किया कि भारत की सैन्य क्षमताएं पूरी तरह रक्षात्मक हैं और उनका निर्धारण देश की सुरक्षा संबंधी जरूरतों के आधार पर होता है। उन्होंने कहा कि ये क्षमताएं किसी अन्य देश को निशाना बनाकर हासिल नहीं की गईं। उन्होंने कहा, “हमने तनाव बढ़ने को लेकर जताई गई चिंताओं को सुना है और ये चिंताएं जायज हैं। हालांकि, किसी देश की मंशा का सही आकलन उसके समय के साथ किए गए आचरण से ही किया जा सकता है। परमाणु हथियारों को शासन—संचालन का सामान्य साधन नहीं माना जाना चाहिए।”

डोनाल्ड ट्रंप ने केटी जकारिया को बनाया व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी मीडिया कंपनी की संचार सलाहकार केटी जकारिया व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव होंगी। वह कैरोलिन लीविट की जगह लेंगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर जकारिया के चयन की जानकारी दी। जकारिया इस मंच का संचालन करने वाली कंपनी ‘ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप’ में ‘कमेंटेटर’ हैं। जकारिया ने इस साल की शुरुआत में कुछ समय के लिए गृह सुरक्षा विभाग की प्रवक्ता के रूप में भी काम किया था। ट्रंप ने कहा कि जकारिया राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके प्रचार अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रही थीं। खासकर, उन्होंने महत्वपूर्ण राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी निभाई थी। जकारिया से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से तत्काल कोई जवाब नहीं मिला। ‘लिव्कडइन’ पर उपलब्ध उनकी प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने पेपरडाइन विश्वविद्यालय रं विधि की डिग्री हासिल की है। कैरोलिन लीविट ने 12 अगस्त को पद छोड़ने की घोषणा की थी और 27 अगस्त को यह पद छोड़ दिया था।

बाल शोषण के मामले में रोहन राणे को पेरिस की अदालत ने सुनाई 20 साल जेल की सजा

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में बच्चों का उत्पीड़न करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क में संलिप्तता के मामले में एक भारतीय युवक को शुक्रवार को पेरिस में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस नेटवर्क पर बच्चों को हिंसक और यौन गतिविधियों वाले वीडियो बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। ‘द एक्सिप्टेड प्रेस’ के पास मौजूद अदालती दस्तावेजों के अनुसार, बाल पीड़ितों को ऑनलाइन मंच ‘डिस्कॉर्ड’ के जरिए इस नेटवर्क में शामिल किया गया था, ताकि उन्हें ‘सीवीएलटी’ नामक समूह का ‘गुलाम’ बनाया जा सके। इस समूह के कम से कम तीन अन्य सदस्यों को अमेरिका में गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिका के पांच पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हिप्पोलिट मारकेटी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन गिरोह के सदस्यों में से एक रोहन राणे (29) को नाबालिग से यौन उत्पीड़न और यातना देने के कृत्यों का दोषी पाया गया। राणे को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जो उस पर लगे आरोपों के तहत अधिकतम सजा है। अदालत में मौजूद लोगों के अनुसार, शुक्रवार रात अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने का फैसला सुनाए जाने पर राणे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बच्चों के साथ दुर्य्वहार से जुड़े इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायाधीशों ने एक असामान्य कदम उठाते हुए मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में करने का आदेश दिया था। अमेरिकी अधिकारियों से मिली सूचना के बाद, 2021 में फ्रांस के दक्षिणी शहर एंटीब में पुलिस ने राणे को गिरफ्तार किया था। अमेरिका के पांच पीड़ितों की ओर से पैरवी कर रहे वकील मारकेटी ने कहा, “पीड़ितों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर गई है।” राणे के वकील ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए भेजे गए अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। मूलरूप से महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला राणे उस समय फ्रांस में पढ़ाई कर रहा था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने प्रत्यर्पण पर विचार करने से पहले फ्रांस में उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने का फैसला किया।

ब्राजील के कुरीतिबा में स्कूल में 13 बच्चों को बंधक बनाने वाला हमलावर पुलिस कार्रवाई में डेर

ब्राजील के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक शहर के एक स्कूल में 13 बच्चों को दो घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाने वाला एक संदिग्ध पुलिस कार्रवाई में मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी भी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह घटना साओ पाउलो से 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कुरीतिबा शहर के साओ ब्राज नामक मध्यमवर्गीय इलाके में हुई। पराना राज्य पुलिस की प्रवक्ता लेटिशिया मार्टिन्स ने विद्यालय ‘सीएम्आई साओ ब्राज’ के बाहर संवाददाताओं को बताया कि संदिग्ध एक कक्षा में घुस गया और बच्चों तथा कर्मचारियों को दो घंटे तक बंधक बनाए रखा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में संदिग्ध को मार गिराया गया। मार्टिन्स ने कहा, “(संदिग्ध ने) खुद पर और दूसरों पर पेट्रोल छिड़कने की धमकी भी दी थी। हमारी टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन अंत में उसे मार गिराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।” उन्होंने यह भी नहीं बताया कि संदिग्ध ने ऐसा क्यों किया।

स्थानीय समाचार माध्यमों में प्रसारित वीडियो में संदिग्ध और पुलिस के बीच बातचीत के दौरान विद्यालय के बाहर अभिभावक रोते—बिलखते दिखाई दे रहे हैं। दो धमाकों के कुछ ही मिनट बाद पुलिसकर्मी बच्चों को विद्यालय से बाहर निकालते नजर आए।

डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, अमेरिका को वुरंत 3 लाख टन डीजल देगा रूस
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद घोषणा की कि रूस अमेरिका को तुरंत डीजल की आपूर्ति करेगा। यह अप्रत्याशित घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका में एक कानून के तहत रूसी तेल और गैस के प्रमुख खरीदारों पर भारी शुल्क लगाने का प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है।

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरांज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर
289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईनं/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।